सिविल सेवा परीक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ साप्ताहिक समसामयिक पत्रिका

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

मई 2021 | अंक 01

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

www.dhyeyaias.com

ध्येय IAS : एक परिचय

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सी.ई.ओ.

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Perfect 7 : एक परिचय

कुरबान अली
मुख्य संपादक

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।
इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

आशुतोष सिंह
प्रबंध संपादक

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।
हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है।
इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक रूप से आपके सामने लाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।
'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके, बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

प्रस्तावना

हमने 'PERFECT 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'PERFECT 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'PERFECT 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'PERFECT 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय IAS

संघ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने 'PERFECT 7' पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 'PERFECT 7' पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका,फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त 'PERFECT 7' पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय IAS

ध्येय टीम

- संस्थापक एवं सी.ई.ओ. — विनय कुमार सिंह
- प्रबंध निदेशक — क्यू. एच. खान
- मुख्य संपादक — कुरबान अली
- प्रबंध संपादक — आशुतोष सिंह
- संपादक — जीत सिंह, अवनीश पाण्डेय, ओमवीर सिंह चौधरी
- मुख्य लेखक — अजय सिंह, अहमद अली, स्नेहा तिवारी
- लेखक — अशरफ अली, गिरराज सिंह, हरिओम सिंह, अंशुमान तिवारी
- समीक्षक — रंजीत सिंह, रामयश अग्निहोत्री
- आवरण सज्जा एवं विकास — संजीव कुमार झा, पुनीश जैन
- विज्ञापन एवं प्रोन्नति — गुफरान खान, राहुल कुमार
- प्रारूपक — कृष्ण कुमार, कृष्णकांत मंडल, मुकुन्द पटेल
- कार्यालय सहायक — हरीराम, राजू यादव

ध्येयIAS
most trusted since 2003

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi-110009

सिविल सेवा परीक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ साप्ताहिक समसामयिक पत्रिका

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

मई 2021 | अंक 01

विषय सूची

सप्ताह के प्रमुख मुद्दे	1-15
सप्ताह के चर्चित व्यक्ति	16-18
सप्ताह के चर्चित स्थान	19-21
सप्ताह के प्रमुख राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय दिवस	22-24
सप्ताह के प्रमुख तथ्य	25-26
स्वयं को जाँचें (वस्तुनिष्ठ प्रश्न)	27-31
स्वयं को जाँचें (विषयनिष्ठ प्रश्न)	32-33

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali (Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

सप्ताह के प्रमुख मुद्दे

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

- माउंटेन्स टू मैंग्रोव्स - अ जर्नी ऑफ 1000 किलोमीटर
- जलवायु परिवर्तन के चलते पृथ्वी की धुरी में आ रहा बदलाव

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021
- भारत- यूनाइटेड किंगडम वर्चुअल शिखर सम्मेलन
- प्रतिरक्षण रणनीति- 2030
- जी-7 देशों द्वारा चीन के विरुद्ध सामूहिक मोर्चा बनाने का प्रयास
- संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग
- मीडिया को अदालत की कार्यवाही की रिपोर्टिंग करने का अधिकार: सर्वोच्च न्यायालय
- सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता
- भारत-जापान संबंध

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में रणनीतिक विनिवेश
- नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम
- वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट - 2021
- एशियाई विकास आउटलुक - 2021
- प्रयुक्त खाद्य तेल आधारित बायोडीजल
- पार्कर सोलर प्रोब

सामान्य अध्ययन-1

भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल तथा समाज

1. "माउंटेन्स टू मैंग्रोव्स - अ जर्नी ऑफ 1000 किलोमीटर"

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत सरकार ने "माउंटेन्स टू मैंग्रोव्स- अ जर्नी ऑफ 1000 किलोमीटर" (Mountains to Mangroves – A Journey of 1000 Kilometers) नामक वेबीनार आयोजित किया है।

प्रमुख बिन्दु

- भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने 'देखो अपना देश' (Dekho Apna Desh) की वेबीनार श्रृंखला के अंतर्गत "माउंटेन्स टू मैंग्रोव्स - अ जर्नी ऑफ 1000 किलोमीटर" (Mountains to Mangroves – A Journey of 1000 Kilometers) नामक वेबीनार आयोजित किया है।
- इस वेबीनार में पर्वतों से मैंग्रोव तक 1000 किलोमीटर की यात्रा दो राज्यों- पश्चिम बंगाल और सिक्किम- पर केंद्रित थी। उल्लेखनीय है कि ये दोनों राज्य पर्यटन की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करते हैं, जिसमें साहसिक, आध्यात्मिकता, विरासत, वन्य जीवन और कई अन्य विशेषताएं शामिल हैं।
- यह यात्रा हिमालय पर्वतश्रेणी के सिक्किम से शुरू होकर पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग होते हुए दक्षिण में तटीय क्षेत्र में स्थित गंगा के मैदानों से विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन में पूरी हुई।

सिक्किम राज्य में प्राकृतिक विपुलता

- भारत का सिक्किम राज्य प्राकृतिक रूप से काफी धनी या विपुल है। इसमें विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंघा, फूलों की अल्पाइन घास के मैदान और पहाड़ी झीलें आदि शामिल हैं। सिक्किम के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में राज्य की राजधानी गंगटोक, पेलिंग, लाचुंग, लाचेन, युमथांग, नाथूला दर्रा, गुरुडोंगमार झील आदि हैं। गौरतलब है कि विदेशियों को सिक्किम जाने के लिए पहले इनर लाइन परमिट के रूप में प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आएपी) लेना जरूरी होता है।

पश्चिम बंगाल में पर्यटन

- भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में समृद्ध इतिहास, अद्भूत परिदृश्य, विरासत वास्तुकला, कला एवं शिल्प, जीवंत लोक उत्सव, संगीत-थिएटर-नाटक, पारंपरिक उत्सव, स्वादिष्ट खानपान आदि की प्रचुरता है। इस राज्य में आकर्षक स्थलों की सूची अंतहीन हैं। इनमें कुछ स्थल के नाम इस प्रकार हैं- दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे (यूनेस्को विश्व विरासत स्थल), कलिम्पोंग, दुआर्स, जाल्दापारा, मालदा, बिष्णुपुर, शांतिनिकेतन, कोलकाता-सिटी ऑफ जॉय, सुंदरबन (यूनेस्को विश्व विरासत स्थल) और दीघा समुद्री तट।

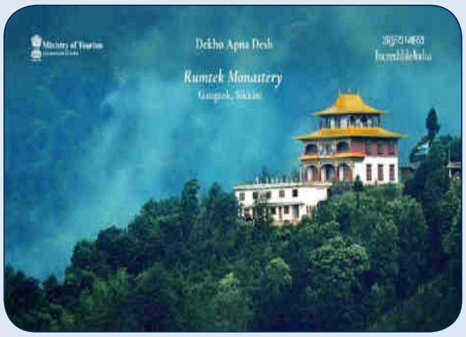

सुंदरबन के बारे में

- सुंदरबन, गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा में स्थित है। यह एक दलदलीय वन क्षेत्र है। यह भारत (पश्चिम बंगाल) और बांग्लादेश दोनों ही देशों में विस्तृत है। सुंदरबन, यहाँ के जंगलों में पाए जाने वाले सुन्दरी नामक वृक्षों के कारण प्रसिद्ध है। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य क्षेत्र में स्थित सुंदरबन को यूनेस्को (UNESCO) द्वारा विश्व धरोहर स्थल (World Heritage site) घोषित किया गया है। सुंदरबन, जैव विविधता की दृष्टि से काफी सम्पन्न क्षेत्र है। इसको रॉयल बंगाल टाइगर के प्राकृतिक आवास के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा, यहाँ एशियाई छोटे पंख वाले ऊदबिलाव, गंगा की डॉल्फिन, भूरे और दलदली नेवले और जंगली रीसस बंदर जैसे महत्वपूर्ण जीव भी पाये जाते हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1973 में सुंदरबन को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था तथा वर्ष 1984 में इसे सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था।

2. जलवायु परिवर्तन के चलते पृथ्वी की धुरी में आ रहा बदलाव

चर्चा का कारण

- अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन (AGU) के 'जर्नल जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में छपे नए शोध के अनुसार 1990 के दशक के बाद से जलवायु परिवर्तन और तापमान में हो रही वृद्धि के चलते दुनिया भर में ग्लेशियर बड़ी तेजी से पिघल रहे हैं जिसका असर पृथ्वी की धुरी पर पड़ रहा है और उसके झुकाव में वृद्धि हो रही है।

पृथ्वी की घूर्णन धुरी या अक्ष

- पृथ्वी पर उत्तर और दक्षिण दोनों ध्रुवों की स्थिति कभी भी स्थिर नहीं रहती है वो लगातार बदलती रहती है पृथ्वी जिस धुरी अथवा अक्ष पर घूमती है, वह काल्पनिक रेखा है, जो पृथ्वी के केंद्र से होकर उसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती है। पृथ्वी का यह अक्ष अपने कक्ष के तल के साथ 66 1/2 डिग्री अंश का कोण बनाता है। पृथ्वी का यह अक्ष सदैव एक ओर ही झुका रहता है।
- पृथ्वी अपनी धुरी पर एक लट्टू की तरह ही घूमती है यदि उसके ऊपरी हिस्से से वजन हटा दिया जाए और दूसरी ओर कर दिया जाए तो उसके घूर्णन अक्ष में भी परिवर्तन हो जाता है।
- नासा के अनुसार, 20 वीं शताब्दी के आंकड़ों से पता चलता है कि पृथ्वी के चक्रण अक्ष (spin axis) में प्रति वर्ष लगभग 10 सेंटीमीटर का विस्थापन होता है। अर्थात, एक सदी में, ध्रुवीय गति 10 मीटर से अधिक होती है।

पृथ्वी की धुरी में बदलाव क्यों?

- पृथ्वी की धुरी में बदलाव क्यों आता है, इसके पीछे बहुत से कारण जिम्मेवार हैं। वैज्ञानिक पहले इसके लिए केवल प्राकृतिक कारकों जैसे महासागरीय धाराओं और पृथ्वी के भीतर गर्म चट्टानों और उनके पिघलने को ही वजह मानते थे। हालांकि 1990 के बाद से जिस तरह से धरती पर ग्लेशियरों में जमा करोड़ों टन बर्फ पिघल रही है, उनसे पृथ्वी के द्रव्यमान का जो वितरण है उसमें बदलाव आ रहा है, जिसका असर इसकी धुरी पर भी पड़ रहा है और उसमें बदलाव आ रहा है।
- इसके अतिरिक्त ध्रुवीय गति में परिवर्तन जलमंडल, वायुमंडल, महासागरों या पृथ्वी में ठोस परिवर्तन के कारण होती है।
- भूजल का बढ़ता दोहन भी इसके पीछे की एक वजह हो सकती है। विश्लेषण के अनुसार कैलिफोर्निया, उत्तरी टेक्सास, बीजिंग और उत्तरी भारत के आसपास के क्षेत्रों में पानी के द्रव्यमान में बड़े बदलावों का पता चला है। गौरतलब है कि यह सभी क्षेत्र अपनी कृषि सम्बन्धी जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर भूजल का दोहन कर रहे हैं।
- चूंकि पीने, उद्योगों या कृषि के लिए हर साल भूमि के नीचे से लाखों टन पानी बाहर निकाला जाता है, और अधिकांश जल अंततः यह समुद्र में शामिल हो जाता है, जिससे ग्रह के द्रव्यमान का पुनर्वितरण होता है।

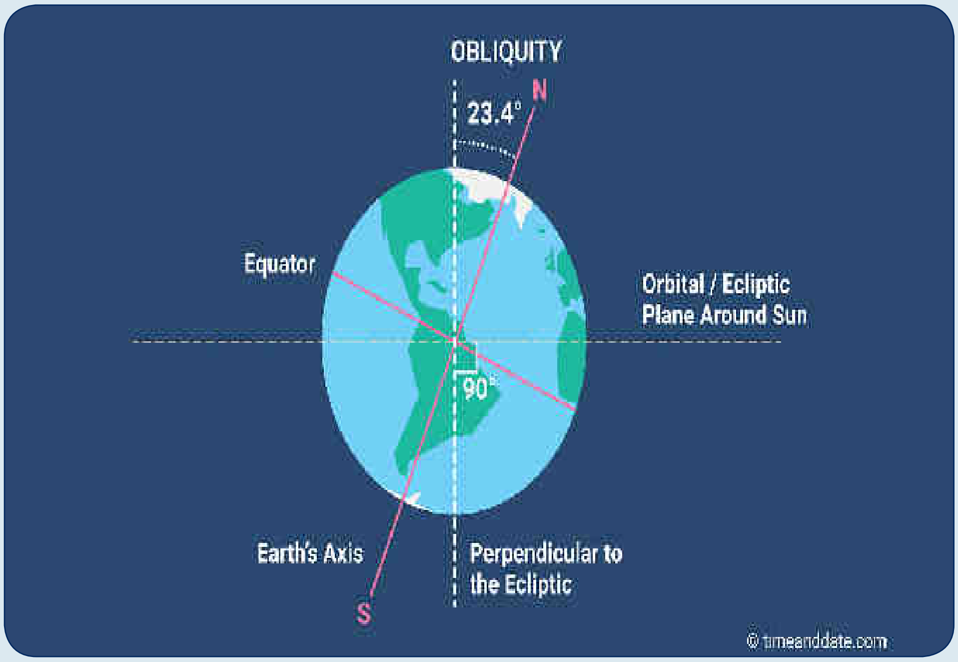

शोध के निष्कर्ष

- जर्नल जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में छपे इस नए शोध के अनुसार 1995 से ध्रुव दक्षिण से पूर्व की ओर खिसक रहे हैं।
- वहीं यदि इनके खिसकने की गति के बारे में बात करें तो वो 1981 से 1995 की तुलना में 1995 से 2020 के बीच 17 गुना ज्यादा तेजी से खिसक रहे हैं।
- 1990 के दशक से, जलमंडल (Hydrosphere) में होने वाले परिवर्तन से उत्तरी ध्रुव, एक नई दिशा में पूर्व की ओर स्थानांतरित हो चुका है।

प्रभाव

- शोधकर्ताओं का मानना है कि पृथ्वी की धुरी में यह जो परिवर्तन आया है वो उतना बड़ा नहीं है कि उसका असर हमारे दैनिक जीवन पर पड़े। इसका असर दिन की अवधि पर केवल कुछ मिलीसेकंड का ही पड़ेगा।
- शोधकर्ताओं के अनुसार यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि किस तरह इंसानी गतिविधियों का प्रत्यक्ष प्रभाव जमीन पर पानी के द्रव्यमान में होने वाले परिवर्तनों पर पड़ रहा है।

सामान्य अध्ययन-2

शासन व्यवस्था, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध

1. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021

चर्चा का कारण

- हाल ही में गृह मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 [Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Act, 2021] के तहत स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी क्षेत्रों में दिल्ली की चुनी हुई सरकार के संवैधानिक और कानूनी जिम्मेदारियों में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ है।

प्रमुख बिन्दु

- हाल ही में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 के प्रभावी होने के बाद भारत सरकार के गृह मंत्रालय का स्पष्टीकरण आया है।
- केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मौजूदा कोविड-19 संकट को संभालने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है क्योंकि शहर में लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना अब भी उसके दायरे में है।
- गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 में संशोधन से दिल्ली में निर्वाचित सरकार के संवैधानिक व विधिक दायित्वों में किसी तरह का बदलाव नहीं आया है, बल्कि यह अधिनियम दिल्ली में और बेहतर शासन सुनिश्चित करेगा।
- दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 किसी भी रूप में दिल्ली की निर्वाचित सरकार के स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सहित अन्य विषयों पर आवश्यक कार्यवाही करने के संवैधानिक व विधिक उत्तरदायित्वों में कोई बदलाव नहीं करता है।
- यह संशोधन अधिनियम दिल्ली की निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल (एलजी) के उत्तरदायित्वों को परिभाषित करेगा और विधायिका व कार्यपालिका के बीच "एक सौहार्दपूर्ण संबंध बनाएगा"।
- दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 को लोकसभा द्वारा 22 मार्च, 2021 और राज्य सभा द्वारा 24 मार्च, 2021 को पारित किए जाने के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा 28 मार्च, 2021 को अनुमोदित किया गया था।
- भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद, यह अधिनियम प्रभावी हो गया है।
- इस संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 21, 24, 33 और 44 में संशोधन किया गया है।

संशोधन अधिनियम के उद्देश्य

- इस संशोधन का उद्देश्य दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 को राजधानी की जरूरतों के लिए अधिक प्रासंगिक बनाना, निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल (एलजी) के उत्तरदायित्व को परिभाषित करना, विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करना, दिल्ली के आम लोगों के लिए बनाई गई योजनाओं तथा कार्यक्रमों का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है।

आलोचना

- दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 की विभिन्न विशेषज्ञों के द्वारा आलोचना भी की जा रही है। कुछ विशेषज्ञों ने इस अधिनियम को लागू करने के समय पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इस संशोधन अधिनियम ने दिल्ली की निर्वाचित सरकार को कमजोर किया है। यह स्थिति कोविड-19 महामारी के नाजुक दौर में दिल्ली की निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल (एलजी) में टकराव को बढ़ा सकती है।

69वाँ संशोधन अधिनियम, 1991

- 69वाँ संशोधन अधिनियम, 1991 के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 239AA और 239AB जोड़े गये थे। इसके तहत केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली या 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' के लिए विशेष उपबंध किए गए थे। 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' के प्रशासक को उपराज्यपाल (Lt. Governor) नाम दिया गया तथा यहाँ विधायिका के गठन का प्रावधान किया गया। विधायिका को लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर सभी मामलों में कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई।

2. भारत- यूनाइटेड किंगडम वर्चुअल शिखर सम्मेलन

चर्चा का कारण

- भारत के प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बीच हाल ही में एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसे भारत- यूनाइटेड किंगडम वर्चुअल शिखर सम्मेलन (India- United Kingdom Virtual Summit) नाम दिया गया है।

प्रमुख बिन्दु

- उल्लेखनीय है कि भारत और यूनाइटेड किंगडम (या ब्रिटेन) के बीच काफी लंबे समय से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं।
- इसके अतिरिक्त, दोनों देश लोकतंत्र, मौलिक स्वतंत्रता एवं कानून के शासन, मजबूत पारस्परिकताओं और निरंतर बढ़ते सामंजस्य के लिए आपसी प्रतिबद्धता पर आधारित रणनीतिक साझेदारी को साझा करते हैं।

'रोडमैप 2030' (Roadmap 2030)

- भारत- यूनाइटेड किंगडम वर्चुअल शिखर सम्मेलन में एक महत्वाकांक्षी 'रोडमैप 2030' (Roadmap 2030) को अपनाया गया, ताकि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाकर 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' (Comprehensive Strategic Partnership) का रूप दिया जा सके। यह रोडमैप अगले दस वर्षों में दोनों देशों के लोगों के बीच पारस्परिक संपर्कों, व्यापार एवं अर्थव्यवस्था, रक्षा व सुरक्षा, जलवायु कार्रवाई और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गहन व मजबूत जुड़ाव का मार्ग प्रशस्त करेगा।

कोविड-19 महामारी में आपसी सहयोग

- दोनों देशों के राजनेताओं ने कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति के खिलाफ लड़ाई में आपसी सहयोग पर भी चर्चा की। उल्लेखनीय है कि भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर चल रही है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम ने भारत की काफी सहायता की है।

'उन्नत व्यापार साझेदारी' (ईटीपी)

- दोनों प्रधानमंत्रियों ने दुनिया की पांचवीं और छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार की संभावनाओं को उन्मुक्त करने के साथ-साथ वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना से भी अधिक करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। इसके लिए 'उन्नत व्यापार साझेदारी' (ईटीपी) का शुभारंभ किया जाएगा। 'उन्नत व्यापार साझेदारी' (ईटीपी) के एक हिस्से के रूप में भारत और यूनाइटेड किंगडम ने एक व्यापक एवं संतुलित एफटीए (मुक्त व्यापार समझौता) पर बातचीत करने के लिए एक रोडमैप पर भी सहमति जताई है। उल्लेखनीय है कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच 'उन्नत व्यापार साझेदारी' (ईटीपी) से दोनों देशों में हजारों प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।

'वैश्विक नवाचार साझेदारी'

- इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भारत व यूनाइटेड किंगडम ने 'वैश्विक नवाचार साझेदारी' की भी घोषणा की है। इसका उद्देश्य चुनिंदा विकासशील देशों को समावेशी भारतीय नवाचारों का हस्तांतरण करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करना है। इस दिशा में शुरुआत अफ्रीका से होगी। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन अनुसंधान और नवाचार संबंधी सहयोग के क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा साझेदार है।

प्रवासन एवं आवाजाही पर एक व्यापक साझेदारी

- भारत और यूनाइटेड किंगडम ने 'प्रवासन एवं आवाजाही पर एक व्यापक साझेदारी' का शुभारंभ किया है जिससे दोनों देशों के बीच विद्यार्थियों एवं प्रोफेशनलों की आवाजाही के लिए और भी अधिक अवसर सुलभ होंगे।

अन्य क्षेत्रों में सहयोग

- दोनों पक्षों ने डिजिटल एवं आईसीटी उत्पादों सहित नई व उभरती प्रौद्योगिकियों पर आपसी सहयोग बढ़ाने और आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने की दिशा में काम करने पर सहमति जताई है। दोनों पक्षों ने रक्षा और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की जिनमें समुद्री क्षेत्र, आतंकवाद का मुकाबला करना और साइबरस्पेस क्षेत्र इत्यादि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, हिंद-प्रशांत और जी-7 में एक-दूसरे के सहयोग पर भी सहमति बनी है।

3. प्रतिरक्षण रणनीति- 2030

चर्चा का कारण

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र और अन्य एजेंसियों द्वारा विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह के दौरान प्रतिरक्षण रणनीति- 2030 (UN's Immunisation Agenda 2030) को लॉन्च किया है। यह संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य सतत् विकास लक्ष्यों (विशेष रूप से सतत् विकास लक्ष्य-3 जिसमें बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण शामिल है) को प्राप्त करने में योगदान देगा। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी ने वैश्विक स्तर पर नियमित टीकाकरण को प्रभावित किया है।

प्रतिरक्षण रणनीति- 2030 क्या है?

- यह 2021-2030 दशक हेतु वैक्सीन और टीकाकरण के लिये एक महत्त्वाकांक्षी, अतिव्यापी वैश्विक दृष्टि और रणनीति निर्धारित करता है।
- प्रतिरक्षण रणनीति- 2030 ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान पर आधारित है। इसका उद्देश्य ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान के उन लक्ष्यों को संबोधित करना है जो 'वैक्सीन दशक' (2011-20) की वैश्विक टीकाकरण रणनीति के हिस्से के रूप में पूरे किये जाने थे।
- ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान को 'वैक्सीन दशक' के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने हेतु विकसित किया गया था, जिससे सभी व्यक्ति और समुदाय वैक्सीन-निवारक बीमारियों से मुक्त हो सकें। यह सात रणनीतिक प्राथमिकताओं के एक वैचारिक ढांचे पर आधारित है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि टीकाकरण, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की प्राप्ति में पूर्णतः योगदान दे।
- इसे चार मुख्य सिद्धांतों द्वारा रेखांकित किया जाता है: यह आम लोगों को केंद्र में रखता है, इसका नेतृत्त्व देशों द्वारा किया जाता है, इसे व्यापक साझेदारी के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, यह डेटा द्वारा संचालित होता है।

प्रतिरक्षण रणनीति- 2030 के लक्ष्य

- इस नए टीकाकरण कार्यक्रम के तहत विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ जैसी अन्य वैश्विक एजेंसियों द्वारा मौजूदा दशक (2021-2030) में 50 मिलियन वैक्सीन-निवारक संक्रमणों से बचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत टीकाकरण से वंचित बच्चों अथवा शून्य-खुराक वाले बच्चों की संख्या को घटाकर 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। शून्य खुराक वाले बच्चों में वे बच्चे शामिल हैं, जिन्हें टीकाकरण कार्यक्रमों के माध्यम से कोई टीका नहीं मिला है। इस कार्यक्रम के तहत बचपन और किशोरावस्था में दिये जाने वाले आवश्यक टीकों का 90% कवरेज लक्ष्य प्राप्त करना भी है। राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर कोविड-19, रोटावायरस या ह्यूमन पेपिलोमावायरस जैसे नए या कम उपयोग किये गए 500 टीकों को प्रस्तुत करने के लक्ष्य को पूरा करना।
- संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियाँ प्रतिरक्षण रणनीति- 2030 के माध्यम से यह सुनिश्चित करना चाहती हैं कि टीकाकरण के लाभों को देशों में सभी के साथ समान रूप से साझा किया जाए।
- '2030 प्रतिरक्षण एजेण्डा' के अनुसार, दुनिया के पास 20 प्राणघातक बीमारियों की रोकथाम के लिये वैक्सीन उपलब्ध हैं। इनके जरिये सभी आयुवर्ग के लोगों के लिये दीर्घ व स्वस्थ जीवन जीना सम्भव हुआ है, और यह उनका अधिकार है। इसे ध्यान में रखते हुए, 'प्रतिरक्षण एजेण्डा 2030' रणनीति के माध्यम से, कोविड-19 व्यवधान से पुनर्बहाली को सहारा देने की बात कही गई है।

जनसंख्या के अनुसार प्राथमिकता

- प्रतिरक्षण रणनीति- 2030 'बॉटम-अप' दृष्टिकोण पर आधारित है, जबकि ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान 'टॉप-डाउन' दृष्टिकोण पर आधारित है। यह आबादी के उस हिस्से को प्राथमिकता देगा जिन तक वर्तमान में टीकाकरण की पहुंच संभव नहीं है, विशेष रूप से समाज का वह वर्ग जो सर्वाधिक हाशिये पर है तथा जो अत्यधिक संवेदनशील और संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में रहता हैं।

टीकाकरण हेतु भारत की पहल

- हाल ही में, कोविड -19 महामारी के दौरान नियमित टीकाकरण में शामिल नहीं हो पाने वाले बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कवर करने के उद्देश्य से सघन मिशन इन्द्रधनुष- 3.0 योजना शुरू की गई है।
- वर्ष 1978 में भारत में टीकाकरण कार्यक्रम को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रतिरक्षण कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। वर्ष 1985 में, इस कार्यक्रम को, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के रूप में परिवर्तित किया गया।
- भारत कोवैक्स का प्रमुख आपूर्तिकर्त्ता है, जो कि एक वैश्विक पहल है। इस पहल का उद्देश्य यूनिसेफ, ग्लोबल एलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्युनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा महामारी की तैयारी में जुटे अन्य संगठनों तक कोविड-19 टीकों की समान पहुँच उपलब्ध करना है।
- भारत ने विभिन्न देशों में कोविड वैक्सीन की आपूर्ति करने हेतु 'वैक्सीन मैत्री' पहल भी शुरू की है।

4. जी-7 देशों द्वारा चीन के विरुद्ध सामूहिक मोर्चा बनाने का प्रयास

चर्चा का कारण

- हाल ही में ब्रिटेन की मेजबानी में जी-7 देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा तेजी से मुखर चीन के विरुद्ध एक सामूहिक मोर्चा बनाने की संभावनाओं पर चर्चा की गयी। इसके अतिरिक्त इस सम्मेलन में ईरान और उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रमों पर भी ध्यान केंद्रित किया।
- ब्रिटेन ने इस वर्ष जी-7 देशों की बैठक में भारत को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया था। वहीं भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को भी अतिथि देश के रूप में निमंत्रण मिला था।

बैठक के परिणाम

- चीन के बढ़ते सैन्य और आर्थिक दबदबे के साथ ही देश और विदेश में उसके प्रभाव को बढ़ाने की इच्छा ने पश्चिमी लोकतंत्रों को अनावश्यक रूप असहज कर दिया है।
- अमेरिका ने झिंजियांग क्षेत्र के मुद्दे पर चीन पर दबाव बनाने के लिए ब्रिटेन के साथ मजबूत सहयोग (robust cooperation) का वादा किया है, जहां बीजिंग द्वारा एक मिलियन उइगर और अन्य मुसलमानों को कैद किया गया है। अमेरिका ने चीन की इस कार्यवाही को नरसंहार करार दिया है। इसके अतिरिक्त चीन की हांगकांग नीति व वहाँ के नागरिकों के बुनियादी अधिकारों से जुड़े मुद्दे पर भी जी-7 देशों द्वारा चिंता जताई गयी है।
- ब्रिटेन ने कहा कि वर्ष 1997 में उसने अपने उपनिवेश हांगकांग को चीन को सौंपे दिये थे। उस वक्त चीन ने हांगकांग के लिए एक अलग प्रणाली का वादा किया था। किन्तु चीन ने अब तक ऐसा नहीं किया है। ब्रिटेन ने हांगकांग के मुद्दे पर बीजिंग से उसकी प्रतिबद्धताओं का पालन करने की मांग की है।
- बैठक में शामिल देशों ने 'चीन के साथ काम करने के लिए, जलवायु परिवर्तन सहित, जहाँ भी संभव हो, रचनात्मक तरीके खोजने के लिए समझदारी और सकारात्मक तरीके खोजने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की।

जी-7 और भारत

- जी-7 के विदेश और विकास मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि ऐसे समय में जब भूराजनीतिक व्यवस्था में तेजी से बदलाव आ रहा है, ज्यादा पारदर्शिता बहुत जरूरी है।
- विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ भारत का संबंध बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है। नई दिल्ली ने बीजिंग को स्पष्ट कर दिया है कि दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों के लिए सीमा पर शांति बहुत जरूरी है।

जी-7

- शुरुआत में यह छह देशों का समूह था, जिसकी पहली बैठक 1975 में हुई थी। अगले साल कनाडा इस समूह में शामिल हो गया और इस तरह यह जी-7 बन गया।
- जी-7 दुनिया की सात सबसे बड़ी कथित विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमरीका शामिल हैं। इसे ग्रुप ऑफ सेवन (group of seven) भी कहते हैं।
- समूह खुद को 'कम्यूनिटी ऑफ वैल्यूज' यानी मूल्यों का आदर करने वाला समुदाय मानता है। स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन और समृद्धि और सतत विकास, इसके प्रमुख सिद्धांत हैं।
- जी-7 देशों के मंत्री और नौकरशाह आपसी हितों के मामलों पर चर्चा करने के लिए हर साल मिलते हैं। प्रत्येक सदस्य देश बारी-बारी से इस समूह की अध्यक्षता करता है और दो दिवसीय वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है।
- सम्मेलन में भाग लेने वाले लोगों में जी-7 देशों के राष्ट्र प्रमुख, यूरोपीयन कमीशन और यूरोपीयन काउंसिल के अध्यक्ष शामिल होते हैं।

5. संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग

चर्चा का कारण

- हाल ही में मणिपुर उच्च न्यायालय ने म्याँमार के सात नागरिकों को नई दिल्ली स्थित संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग (United Nations High Commissioner for Refugees- UNHCR) के समक्ष जाने की अनुमति दी है। गौरतलब है कि इन 7 लोगों ने फरवरी में म्याँमार में सैन्य तख्तापलट के बाद गुप्त रूप से भारत में प्रवेश किया था।

मणिपुर उच्च न्यायालय की टिप्पणी

- उच्च न्यायालय ने कहा कि यद्यपि भारत संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमयों का पक्षकार नहीं है, किन्तु वह 1948 के मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (Universal Declaration of Human Rights-UDHR) और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार नियम' (International Covenant on Civil and Political Rights), 1966 का हस्ताक्षरकर्ता है।
- उच्च न्यायालय ने कहा कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा दूरगामी और असंख्य सुरक्षा प्रदान की गयी है जिसकी व्याख्या समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गयी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 21 में शरणार्थियों को उनके मूल-देश में वापस नहीं भेजे जाने (Non-Refoulement) का अधिकार प्राप्त है।

- गौरतलब है कि नॉन-रिफाउलमेंट (Non-Refoulement) अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत एक ऐसा सिद्धांत है जिसके तहत अपने देश से उत्पीड़न या सताने (persecution) की वजह से भागने वाले व्यक्ति को वापस उस देश में लौटने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

भारत - म्यांमार सीमा

- भारत और म्यांमार की सीमाएं आपस में लगती हैं जिनकी लंबाई 1600 किमी से भी अधिक है तथा बंगाल की खाड़ी में एक समुद्री सीमा से भी दोनों देश जुड़े हुए हैं।
- अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड की सीमा म्यांमार से सटी हुई है।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग

- संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग की स्थापना 14 दिसम्बर, 1950 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। इसका मुख्यालय जिनेवा (Geneva) में स्थित है।
- संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का कार्य क्षेत्र दुनिया भर में शरणार्थियों के संरक्षण और शरणार्थी समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का नेतृत्व और उसमें समन्वय करना है।
- इसका मूल उद्देश्य शरणार्थियों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना है। यूएनएचसीआर यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करता है कि हर कोई किसी दूसरे देश में शरण मांगने और सुरक्षित शरण पाने के अधिकार का उपयोग कर सके। उसे स्वेच्छा से स्वदेश लौटने, स्थानीय समुदाय में घुलमिल जाने अथवा किसी तीसरे देश में बस जाने का विकल्प भी मिले।
- यूएनएचसीआर को राष्ट्रविहीन लोगों की मदद करने का काम भी सौंपा गया है।

6. मीडिया को अदालत की कार्यवाही की रिपोर्टिंग करने का अधिकार: सर्वोच्च न्यायालय

चर्चा का कारण

- हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने देश में कोविड-19 के मामले बढ़ने के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराने वाली मद्रास उच्च न्यायालय की टिप्पणियों को हटाने से इनकार कर दिया। साथ ही, मीडिया को न्यायिक कार्यवाही के दौरान टिप्पणियों की रिपोर्टिंग करने से रोकने का अनुरोध भी ठुकरा दिया। न्यायालय ने कहा कि यह एक प्रतिगामी कदम होगा।

मुद्दा क्या था?

- हाल ही में जब पांच राज्यों के चुनाव हुए तब एक मामले की सुनवाई के दौरान मद्रास हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है, ऐसे में उनके अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए।
- अदालत में जब चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि उनकी ओर से कोविड गाइडलाइन्स का पालन किया गया, वोटिंग डे पर नियमों का पालन किया गया था। इसपर अदालत नाराज हुई और पूछा कि जब प्रचार हो रहा था, तब क्या चुनाव आयोग दूसरे ग्रह पर था। चुनाव आयोग द्वारा मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई,जिसमें कहा गया था कि मद्रास हाईकोर्ट की अपमानजनक टिप्पणी को हटाया जाये।
- चुनाव आयोग ने याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट खुद एक संवैधानिक एवं स्वतंत्र संस्था है जबकि चुनाव आयोग भी संवैधानिक संस्था है, इसलिए हाईकोर्ट की इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी से हमारी छवि खराब हुई है। साथ ही, मीडिया को न्यायिक कार्यवाही के दौरान टिप्पणियों की रिपोर्टिंग करने से रोकने का अनुरोध भी चुनाव आयोग द्वारा किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

- न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने माना कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियां कठोर थीं। लेकिन आयोग की आपत्ति जिस टिप्पणी पर है, वह किसी आदेश का हिस्सा नहीं है ऐसे में उसे हटाने की जरूरत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों का अधिकार है कि अदालत उनके समक्ष सही रहे, ऐसे में मीडिया की भूमिका अहम हो जाती है. अगर हम नई मीडिया को रिपोर्टिंग से रोकेंगे, तो इससे कुछ भला नहीं होने वाला है।
- पीठ ने कहा कि अदालतों को मीडिया की बदलती प्रौद्योगिकी को लेकर सजग रहना होगा। उसने कहा कि यह अच्छी बात नहीं है कि उसे न्यायिक कार्यवाही की रिपोर्टिंग करने से रोका जाए।
- सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दो संवैधानिक संस्थाओं के बीच अधिकारों का संतुलन बना रहना उतना ही जरूरी है, जितनी मीडिया की स्वतंत्रता जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुनिया में कई अदालत हैं जो लाइव स्ट्रीमिंग करती हैं, ताकि लोग उनसे जुड़ सकें। किसी सुनवाई के दौरान जब कोई राय दी जाती है, तो वह किसी फैसले को निर्धारित नहीं करती है।
- मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी की प्रकृति पर, शीर्ष अदालत ने कहा कि "कुछ सर्तकता और सावधानी से वर्तमान मामले में समस्याओं को दूर किया जा सकता था।

7. सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता

चर्चा का कारण

- भारत दुनिया के सबसे बड़े कल्याणकारी राज्यों में से एक है और फिर भी वह COVID-19 के कारण, अपने सबसे कमजोर नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहा है। COVID-19 महामारी के कारण, भारत में बड़े पैमाने पर अंतर्राज्यीय प्रवासन के साथ साथ खाद्य असुरक्षा में बढ़ोतरी हुई। इसके अतिरिक्त देश में स्वास्थ्य ढाँचा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जानकारों के अनुसार सामाजिक पूंजी की अनुपस्थिति में आर्थिक पूंजी कमजोर वर्ग तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच बनाने में अपर्याप्त साबित हुई है।

आवश्यकता क्यों?

- कोरोना महामारी ने लगभग 75 मिलियन लोगों को गरीबी में धकेल दिया है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने मध्यम और उच्च वर्ग के नागरिकों को भी बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। ऐसे में सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता महसूस हो रही है।
- भारत में 500 से अधिक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजनाएँ (direct benefit transfer schemes) हैं जो केंद्र एवं राज्यों द्वारा संचालित होती हैं। हालाँकि ये योजनाएँ पूरी तरह से उन लोगों तक नहीं पहुँच पायी हैं जो जरूरतमंद हैं।
- इसके अतिरिक्त महामारी से पता चला है कि हमारी मौजूदा योजनाओं का लाभ उठाना और सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमारी कमजोर आबादी पर बाहरी आघात के प्रभाव को अवशोषित करने में मदद करेगा।
- मौजूदा सामाजिक सुरक्षा कानून के दायरे से करीब 90 फीसदी श्रमबल बाहर है जो मुख्य तौर पर असंगठित क्षेत्र के हैं।
- सामाजिक सुरक्षा प्रणाली भारत में अकल्पनीय नहीं है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के तहत ने भारत ने सफलतापूर्वक पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम चलाया और 2014 में, भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। यह प्रयास हमें दिखाता है कि सामाजिक कल्याण के लिए कम समय सीमा में भी सफलता पायी जा सकती है।

सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा क्या है?

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा विभिन्न प्रकार की अवांछित गतिविधियों के प्रभावों के खिलाफ पीड़ितों की रक्षा करता है। यह एक व्यापक दृष्टिकोण है जो सामाजिक जोखिम को रोकने के लिये विकसित की गई है। यह व्यक्ति को किसी भी प्रकार की अनिश्चितताओं में अपने पर आश्रित लोगों के लिये एक बुनियादी न्यूनतम आय का आश्वासन प्रदान करता है।
- सामाजिक जोखिम में सेवानिवृत्ति, बीमारी, विकलांगता, वृद्धावस्था, उत्तरजीवी, कमाने वाले सदस्यों की मृत्यु, मातृत्व, बेरोजगारी आदि शामिल हैं।

सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा से लाभ

- भारत में मौजूदा योजनाएँ कई प्रकार के सामाजिक सुरक्षा को कवर करती हैं। हालांकि ये योजनाएँ विभिन्न विभागों के अंतर्गत कई उप-योजनाओं में बंटी हुई हैं। इसके अतिरिक्त डेटा संग्रह की खामियों की वजह से यह योजनाएँ अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाती हैं। एक सार्वभौमिक प्रणाली होने से एक डेटाबेस के तहत सभी लाभार्थियों के आँकड़ों को एकत्रित कर सेवाओं के वितरण में आसानी होगी। उदाहरण के लिये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana) एक ऐसी योजना है जिसे सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा के रूप में जाना जाता है।
- यह पहले से विद्यमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), गैस सिलेंडरों के प्रावधान और मनरेगा (MGNREGS) के लिये मजदूरों के आँकड़े को समेकित करता है।
- आम तौर पर सामाजिक सहायता योजनाओं को आवश्यकताओं के मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है। एक सार्वभौमिक सुरक्षा योजना के होने से कोई भी व्यक्ति सामाजिक रूप से मूलभूत योजनाओं से वंचित नहीं रहेगा।
- उदाहरण के लिए, पीडीएस को राशन कार्ड की अनुपस्थिति में एक सार्वभौमिक पहचान पत्र जैसे आधार या मतदाता कार्ड से जोड़ा जा सकता है। पीडीएस को राशन कार्ड की अनुपस्थिति में एक सार्वभौमिक पहचान पत्र जैसे आधार या मतदाता कार्ड से जोड़ा जा सकता है। यह उन सभी को लाभान्वित करेगा जिन्हें खाद्यान्न की आवश्यकता है।
- यह विशेष रूप से प्रवासी आबादी के लिए उपयोगी होगा। अन्य योजनाओं/कल्याणकारी प्रावधानों जैसे कि शिक्षा, मातृत्व लाभ, विकलांगता की स्थिति में लाभ आदि को भी सार्वभौमिक बनाने से लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है।

आगे की राह

- राज्य और केंद्र की योजनाओं के मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। कल्याणकारी वितरण में दोहराव, समावेशन और बहिष्करण त्रुटियों से बचने के लिए मौजूदा खामियों को भी दूर करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही कमजोर समूहों के लिए कल्याण पहुंच की लागत को जानने के लिए एक अध्ययन आयोजित किया जा सकता है।
- सरकारी विभागों में डेटा डिजिटलीकरण, डेटा-चालित निर्णय लेने और सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने से सामाजिक कल्याण को बढ़ावा दिया जा सकता है।

8. भारत-जापान संबंध

चर्चा का कारण

- हाल ही में अमेरिका यात्रा के दौरान जापान के प्रधान मंत्री योशिहिदे सुगा ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र की महत्ता पर बल देते हुए कहा कि मुक्त एवं स्वतंत्र हिंद-प्रशांत क्षेत्र (FOIP) जापान की प्राथमिकताओं में से एक है। गौरतलब है कि हाल के महीनों में, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और जापान ने अपने साझा रणनीतिक हितों को तेजी से बढ़ावा देने की कोशिश की है।
- टोक्यो और वाशिंगटन ने दक्षिण और पूर्वी-चीन सागर के साथ-साथ ताइवान स्ट्रेट के क्षेत्रीय विवादों में चीन के आक्रामक दृष्टिकोण को संबोधित किया है।

अमेरिका-जापान वार्ता के मुख्य बिंदु

- अमेरिका-जापान ने अपनी उन संधि को दोहराया जो पूर्वी-एशिया में लंबे समय तक स्थिरता का स्रोत रही। दोनों पक्षों ने विवादित सेनकाकू द्वीप और ताइवान जैसे प्रमुख क्षेत्रीय मुद्दों पर एक साथ खड़े होने का वादा भी किया।
- इसके अलावा संघर्ष की बदलती हुई प्रकृति को देखते हुए दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोग के माध्यम से इन क्षेत्रों में चीन की विस्तृत शक्तियों का मुकाबला करने के लिए विस्तृत चर्चा भी की।
- दोनों पक्षों द्वारा 5 जी और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी नई प्रौद्योगिकियों के विकास पर हावी होने के लिए चीनी महत्वाकांक्षाओं पर भी चर्चा की गयी। इसके अतिरिक्त नई उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में 1.4 ट्रिलियन डॉलर का निवेश करने की चीन की हालिया घोषणा को देखते हुए दोनों पक्षों ने 'कंपटेटिव एंड रीजिलिंसस पार्टनरशिप (Competitiveness and Resilience Partnership- CoRe) की घोषणा करके इस खाई को पाटने का संकल्प लिया।
- दोनों देशों ने बार-बार स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक के अपने दृष्टिकोण पर जोर दिया, जो कानून के शासन, नेविगेशन की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक मानदंडों और विवादों को निपटाने के लिए शांतिपूर्ण साधनों के उपयोग का सम्मान करता है। इसके अतिरिक्त दोनों देशों ने क्वाड समूह के लिए अपना निरंतर समर्थन व्यक्त किया।

भारत-जापान संबंध

- जापान पिछले कई दशकों से अपनी ऑफिशियल डेवेलपमेंट असिस्टेंस (ओडीए) नीति के तहत जरूरतमंद और मित्र देशों को अनुदान देता रहा है। पिछले दो दशकों में भारत पर उसने खासा ध्यान दिया है।
- 2014 में एक्ट ईस्ट नीति के लॉन्च होने से आए परिवर्तनों और भारत जापान के संबंधों में आयी निकटता से दोनों देशों के बीच आर्थिक और निवेश संबंधी रिश्ते भी बेहतर हुए हैं। मिसाल के तौर पर 2018 में ही भारत सबसे ज्यादा जापानी ओडीए निवेश प्राप्त करने वाला देश बन गया था।
- पिछले एक दशक में भारत को आवंटित ओडीए अनुदान लगातार बढ़ता ही गया है। जापानी अनुदान और निवेश का दौर अभी भी बरकरार है जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी जैसे सेक्टरों के लिए बहुत बड़ी सहूलियतें लेकर आ रहा है। मेट्रो रेल परियोजनाएं हों या दिल्ली-मुंबई कारिडोर या फिर उत्तरपूर्व के प्रदेशों में निवेश, जापान ने तत्परता से भारत की क्षमता बढ़ाने संबंधी परियोजनाओं में निवेश किया है।
- इंडो-पेसिफिक क्षेत्रीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात हो या अमेरिका, जापान, और आस्ट्रेलिया के साथ चार-देशीय क्वाड की सामरिक संरचना हो, भारत और जापान एक दूसरे के स्वाभाविक साझेदार बन चुके हैं। यही नहीं चीन की आर्थिक शक्ति के खिलाफ सप्लाई चेन रेजीलियेंस इनीशिएटिव और पिछड़े अफ्रीकी और एशियाई देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए बने एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, सभी भारत और जापान की दोस्ती की मजबूत बुनियाद पर खड़े हैं।
- बीते कुछ वर्षों में भारत और जापान ने दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिये दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों की नीति का समर्थन किया है।

अंडमान-निकोबार में जापान का निवेश

- जापान ने अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 265 करोड़ रुपये के अनुदान का निर्णय लिया है। इन अनुदानों के तहत दक्षिण अंडमान में सौर ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल और बिजली सिस्टम को स्टेबिलाइज करने की योजना है जिसके तहत 15 मेगावाट की बैटरियों की खरीद भी होगी।
- जापान के नजरिए से देखें तो अंडमान-निकोबार द्वीप समूह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके अच्छी तरह विकास से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि उसके सभी मित्र देशों, खास तौर पर क्वाड के साथियों अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया और पड़ोसी मित्रों को अच्छी मदद हासिल हो सकती है, चाहे जहाजों की डॉकिंग हो या हिंद महासागर में अचानक किसी मदद की जरूरत, अंडमान-निकोबार बहुत काम आ सकता है। जापान को इस बात का अच्छी तरह अंदाजा है कि मलक्का स्ट्रेट से निकला हर वो जहाज जो हिंद महासागर की ओर जाएगा, उसे अंडमान-निकोबार के नजदीक से होकर गुजरना ही पड़ेगा। यहां से गुजरने वाले चीन के हर जहाज पर नजर रखी जा सकेगी।
- अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह भारत की दक्षिणतम सीमा पर स्थित है। यह भारत को न सिर्फ हिंद महासागर और इंडो-पैसिफिक से जोड़ता है बल्कि दक्षिणपूर्व एशिया से भी भारत का सीधा संपर्क भी है। रणनीतिक तौर पर अंडमान-निकोबार भारत को इंडोनेशिया से जोड़ता हैं। यदि अंडमान-निकोबार के नजरिए से भारत के पड़ोसियों को देखा जाय तो श्रीलंका और बांग्लादेश के अलावा इंडोनेशिया, थाईलैंड और म्यांमार भारत के सबसे नजदीक के पड़ोसियों में आते हैं। यह तीनों ही देश भारत की एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत भी आते हैं और इस लिहाज से अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिए दक्षिणपूर्व एशिया के द्वार के तौर पर काम कर सकता है, खास तौर पर नौसैनिक और समुद्री संपर्क के मामले में।

क्वाड

- द क्वॉड्रिलैटरल सिक्यॉरिटी डायलॉग (क्वॉड) की शुरुआत वर्ष 2007 में हुई थी। क्वाड में चार देश अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं। क्वाड के तहत प्रशांत महासागर, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में फैले विशाल नेटवर्क को जापान और भारत के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

सामान्य अध्ययन-3

प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव-विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा-प्रबंधन

1. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में रणनीतिक विनिवेश

चर्चा का कारण

- हाल ही में कैबिनेट ने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (IDBI Bank Limited) esa j.kuhfrd fofuos'k(strategic disinvestment) और प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण (transfer of management control) को मंजूरी दे दी है।

मुख्य बिन्दु

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs) ने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में रणनीतिक विनिवेश के साथ-साथ प्रबंधन नियंत्रण (management control) के हस्तांतरण को भी अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
- भारत सरकार और एलआईसी (LIC) द्वारा बेची जाने वाली अपनी-अपनी हिस्सेदारी की सीमा का निर्धारण आरबीआई के परामर्श से इस सौदे को उपयुक्त स्वरूप देने के समय किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि भारत सरकार और एलआईसी के पास आईडीबीआई बैंक की 94% से भी अधिक इक्विटी (भारत सरकार 45.48%, एलआईसी 49.24%) है।
- एलआईसी ही वर्तमान में प्रबंधन नियंत्रण के साथ आईडीबीआई बैंक की प्रमोटर है और भारत सरकार इसकी सह-प्रमोटर है।

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के रणनीतिक विनिवेश के पक्ष में तर्क

- भारत सरकार का मानना है कि आईडीबीआई बैंक लिमिटेड का रणनीतिक खरीदार कई सुधारात्मक कदम उठाएगा। रणनीतिक खरीदार (strategic buyer), आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की कारोबारी क्षमता के इष्टतम विकास करेगा। इसके अलावा, रणनीतिक खरीदार बैंक के विकास के लिए उसमें आवश्यक धनराशि डालेगा एवं नई प्रौद्योगिकी का उपयोग भी शुरू करेगा। इसके साथ ही आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के रणनीतिक खरीदार द्वारा बैक प्रबंधन से जुड़ी सर्वोत्तम प्रथाओं पर अमल भी किया जाएगा।
- सरकार यह भी उम्मीद कर रही है कि रणनीतिक खरीदार एलआईसी और सरकारी सहायता/धन पर किसी भी निर्भरता के बिना ही अधिक-से-अधिक कारोबार सृजित करेगा। उल्लेखनीय है कि इस रणनीतिक विनिवेश से प्राप्त होने वाले संसाधनों का उपयोग सरकार के विकास कार्यक्रमों का वित्तपोषण करने में किया जाएगा, जिससे देश के नागरिक लाभान्वित होंगे। विनिवेश के जरिए सरकारी कंपनियों को प्रतिस्पर्धी व सक्षम बनाने में भी मदद मिलती है।

क्या है विनिवेश?

- सरकारी कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया विनिवेश कहलाती है। विनिवेश में सरकार अपने हिस्से के शेयर्स को दूसरे निवेशकों को दे देती है। किंतु कई वजहों से संबंधित कंपनी में विनिवेश के बाद भी सरकार का दखल, प्रबंधन में बना रहता है।

क्या है रणनीतिक विनिवेश?

- रणनीतिक विनिवेश में सरकार किसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को इस तरह से हस्तांतरित करती है कि फिर संबंधित कंपनियों के प्रबंधन में दखल का रास्ता नहीं बचता और कंपनी का प्रबंधन पूरे तौर पर निजी हाथों में हस्तांतरित हो जाता है। रणनीतिक विनिवेश का एक उद्देश्य यह भी होता है कि कंपनी के कामकाज में कुशलता लायी जा सके। सरकार के मुताबिक, रणनीतिक विनिवेश से प्राप्त होने वाले संसाधन का उपयोग सामाजिक क्षेत्र की विकास योजनाओं के वित्त पोषण के लिए किया जा सकता है; जिससे देश में विकास की गति तीव्र होगी।

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (IDBI Bank Limited)

- भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (Industrial Development Bank of India-IDBI) को संक्षेप में आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (IDBI Bank Limited) के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। यह बैंक भारतीय उद्योग के विकास के लिए ऋण और अन्य वित्तीय सुविधाएं प्रदान करती है।

2. नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम (NGFS)

चर्चा का कारण

हाल ही में 'नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम' (Network for Greening Financial System-NGFS) में भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) शामिल हुआ है।

'नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम' (Network for Greening Financial System-NGFS)

- 'नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम' (Network for Greening Financial System-NGFS) 83 केंद्रीय बैंकों और वित्तीय पर्यवेक्षकों का एक नेटवर्क है, जिसका उद्देश्य हरित वित्त को बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन के लिए केंद्रीय बैंकों की भूमिका को विकसित करना है।
- 'नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम' (एनजीएफएस) की स्थापना 2017 में हुई थी। दरअसल इस नेटवर्क की शुरुआत वर्ष 2017 में फ्रांस के पेरिस में हुई 'वन प्लैनेट समिट' (One Planet Summit) में की गयी थी। उस समय इस नेटवर्क को 8 संस्थापक केंद्रीय बैंकों द्वारा लॉन्च किया गया था।
- वर्तमान में 'नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम' (एनजीएफएस) के सचिवालय को 'बंक डी फ्रांस' (Banque de France) द्वारा होस्ट किया जाता है।
- उल्लेखनीय है कि एनजीएफएस को 'सेंट्रलबैंकिंग डॉट कॉम' द्वारा वर्ष 2020 की सर्वश्रेष्ठ हरित पहल से सम्मानित किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बारे में

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) देश का केन्द्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1934 के तहत 5 करोड़ रूपए की शुरूआती धनराशि के साथ की गई थी। बाद में, कुछ सीमित लोगों के हाथों में शेयरों के केन्द्रीयकरण को रोकने के लिए 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

आरबीआई के कार्य

- भारतीय रिजर्व बैंक के कई प्रमुख कार्य हैं जैसे कि मौद्रिक नीति तैयार करना, उसको लागू करना और उसकी निगरानी करना; वित्तीय प्रणाली का रेगुलेशन और निगरानी करना; विदेशी मुद्रा का प्रबन्धन करना; मुद्रा जारी करना, उसका विनिमय करना और परिचालन योग्य न रहने पर उन्हें नष्ट करना इत्यादि।
- इसके अलावा, आरबीआई साख नियन्त्रित करने और मुद्रा के लेन-देन को नियंत्रित करने का कार्य तथा सरकार के बैंकर और बैंकों के बैंकर के रूप में भी काम करती है।
- भारतीय रिजर्व बैंक देश में प्रभावी रूप से ऋण को नियंत्रित करने और विनियमन करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक तकनीकों का व्यापक उपयोग करती है।

भारतीय रिजर्व बैंक की संरचना

- रिजर्व बैंक का कामकाज केन्द्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित होता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 8 के अनुसार बोर्ड के सदस्यों को भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- आरबीआई के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सीबीडी (Central Board of Directors) के अंतर्गत आधिकारिक निदेशक और गैर-आधिकारिक निदेशक - दो प्रकार के बोर्ड होते हैं। आधिकारिक निदेशक के अंतर्गत जहाँ एक पूर्णकालिक गवर्नर और अधिकतम चार उप गवर्नर शामिल होते हैं। वहीं गैर आधिकारिक-निदेशक के अंतर्गत सरकार द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों से दस निदेशक और एक सरकारी अधिकारी शामिल होते हैं।

3. वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट - 2021

चर्चा का कारण?

- हाल ही में 'वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट-2021' (Global Forest Goals Report-2021) को जारी किया गया है।

वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट

- 'वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट-2021' (Global Forest Goals Report-2021) को संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएनओ) द्वारा जारी किया गया है।
- 'वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट-2021' को संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (Department of Economic and Social Affairs) द्वारा निर्मित किया गया है।
- 'वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट-2021' में कोविड-19 महामारी के कारण वनों के प्रबंधन में विभिन्न देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों को उल्लिखित किया गया है।
- इसके अतिरिक्त, इस रिपोर्ट में 'संयुक्त राष्ट्र की वनों के लिए रणनीतिक योजना-2030' (United Nations Strategic Plan for Forests-2030) के उद्देश्यों और लक्ष्यों का भी मूल्यांकन किया गया है।

'वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट-2021' के प्रमुख बिन्दु

- 'वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट-2021' में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी ने वनों के प्रबंधन में विभिन्न देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा दिया है।
- वनों पर आश्रित समुदायों को कोविड-19 महामारी ने प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। इस महामारी ने ना सिर्फ वनों पर आश्रित समुदायों को बल्कि समाज के हर तबके को

वैश्विक स्तर पर प्रभावित किया है। कई समुदाय अपनी आजीविका के लिए आज संघर्षरत हैं।

- वनों पर आश्रित समुदायों ने कोविड-19 महामारी के चलते ना सिर्फ अपने रोजगार को खोया है बल्कि उनकी आय में भी कमी आई है।
- इस महामारी ने समाज के संवेदनशील वर्गों (यथा-महिलाएँ आदि) के लिए मौसमी रोजगार में भारी कमी की है।
- ग्रामीण, दूरदराज व दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों (खासकर वनों पर आश्रित समुदाय) को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए यह आबादी इस महामारी के प्रति काफी संवेदनशील हो गई है।
- इसलिए कोविड-19 महामारी वैश्विक स्तर पर सिर्फ एक स्वास्थ्य संकट बनकर नहीं उभरी है, बल्कि इस महामारी ने 'हमारे इच्छित भविष्य' (Future We Want) को हमारी पहुंच से और दूर कर दिया है।
- कोविड-19 महामारी वैश्विक स्तर पर लाखों लोगों की मौत का कारण बन रही है। इसके अलावा, इसने अनगिनत लोगों को निरपेक्ष गरीबी की ओर धकेल दिया है।
- इस महामारी ने वैश्विक स्तर पर खाद्य असुरक्षा को बढ़ा दिया है। इसके अलावा, इसने असमानता की खाई को और बढ़ाया है।
- कोविड-19 महामारी के चलते वर्ष 2020 में विश्व सकल उत्पाद में लगभग 3% तक की गिरावट आई है। वैश्विक महामंदी के बाद, यह विश्व सकल उत्पाद में सबसे बड़ी गिरावट है।
- 'वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट-2021' में वैश्विक स्तर पर जैव विविधता के ह्रास को भी उल्लिखित किया गया है। इसमें बताया गया है कि वनों के विनाश के चलते वैश्विक स्तर पर लगभग एक मिलियन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो चुका है। क्योंकि वर्ष 1980 से 2000 तक उष्णकटिबंधीय वनों का लगभग 100 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल नष्ट हो चुका है।

'वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट-2021' के सुझाव

- कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतियों एवं जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्पन्न चुनौतियों से एकसाथ मिलकर निपटा जा सकता है।
- इसके लिए वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों की राष्ट्रीय सरकारें व अन्य हितधारकों को मिलकर कार्य करना होगा।
- विभिन्न देशों की राष्ट्रीय सरकारें व अन्य हितधारकों को संधारणीय विकास और वन प्रबंधन जैसी प्रथाओं पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।

4. एशियाई विकास आउटलुक - 2021

चर्चा का कारण

- हाल ही में एशियाई विकास बैंक (ADB) ने एशियाई विकास आउटलुक-2021 (Asian Development Outlook-2021) रिपोर्ट को जारी किया है।

प्रमुख बिन्दु

- एशियाई विकास बैंक (ADB) ने एशियाई विकास आउटलुक-2021 (Asian Development Outlook-2021) रिपोर्ट में कहा है कि भारत में इस समय कोविड-19 की दूसरी लहर चल रही है; जो भारत के आर्थिक सुधारों को 'जोखिम' में डाल सकती है।
- हालांकि इस रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 11 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि का अनुमान भी लगाया गया है।
- एशियाई विकास आउटलुक-2021 रिपोर्ट के मुताबिक सार्वजनिक निवेश, टीकाकरण और घरेलू मांग में वृद्धि के कारण भारत में आर्थिक सुधार जारी रहेंगे। जिसके चलते वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर में 11 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है।
- जबकि इस रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी में 7% वृद्धि दर का ही अनुमान लगाया गया है।
- वहीं एशियाई विकास आउटलुक-2021 रिपोर्ट में एशिया महाद्वीप के संदर्भ में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में विकासशील एशिया की आर्थिक वृद्धि दर 7.3% के आसपास रहेगी। उल्लेखनीय है कि पिछले साल यह दर 0.2% रही थी।
- रिपोर्ट के मुताबिक, कोविड-19 महामारी से वैश्विक रिकवरी और इस महामारी के टीकाकरण अभियान की सशक्त शुरुआत का लाभ एशियाई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को भी मिलेगा।

एशियाई विकास आउटलुक (Asian Development Outlook-ADO)

- एशियाई विकास आउटलुक (Asian Development Outlook-ADO) को एशियाई विकास बैंक (ADB) के द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा अपने विकासशील सदस्य देशों (DMCs) के लिए जारी की जाती है।

एशियाई विकास बैंक (ADB) के बारे में

- एशियाई विकास बैंक (ADB) एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसम्बर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गयी थी। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। इस बैंक की स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी। हालांकि वर्तमान में एडीबी के 68 सदस्य हैं; जिसमे से 49 एशिया और पैसिफिक से हैं और 19 सदस्य बाहरी हैं। एडीबी (ADB) का प्रारूप काफी हद तक विश्व बैंक के आधार पर बनाया गया था और विश्व बैंक के समान यहां भी भारित वोट प्रणाली की व्यवस्था है जिसमे वोटों का वितरण सदस्यों के पूंजी अभिदान अनुपात के आधार पर किया जाता है।

एशियाई विकास बैंक की वार्षिक बैठक

- हाल ही में 'एशियाई विकास बैंक' (Asian Development Bank) की वार्षिक बैठक हुई है।

प्रमुख बिन्दु

- 'एशियाई विकास बैंक' (Asian Development Bank) की वार्षिक बैठक में भारत की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाग लिया है।
- भारत की वित्त मंत्री ने एशियाई विकास बैंक की वार्षिक बैठक में कहा कि कोविड-19 महामारी के मौजूदा दौर में कोरोना वैक्सीन पर राष्ट्रवाद नहीं होना चाहिए। उन्होने वैश्विक समुदाय को आगाह किया कि कोरोना वैक्सीन पर राष्ट्रवाद पूरी दुनिया को एक खतरनाक दिशा में ले जाएगा। इसलिए विकसित देशो को कोरोना वैक्सीन के उत्पादन के लिये जरूरी प्रौद्योगिकी साझा करनी चाहिए और इससे जुड़े महत्वपूर्ण उपकरणों एवं कच्चे माल की बेरोक-टोक आवाजाही भी सुनिश्चित करनी चाहिए।
- इसके अलावा, भारत की वित्त मंत्री ने कोविड-19 महामारी के संदर्भ में डबल्यूटीओ के बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े व्यापार संबंधित पहलुओं (ट्रिप्स) पर गौर करने की जरूरत पर भी जोर दिया।
- भारत की वित्त मंत्री ने इस बात पर काफी जोर दिया कि कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिये वैश्विक स्तर पर सबको मिलकर काम करने की जरूरत है।
- कोविड-19 महामारी से संबन्धित मुद्दों के अलावा, उन्होने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) का भी जिक्र किया। वित्त मंत्री ने कहा कि एमएसएमई, भारत जैसी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। यही कारण है कि भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान उनकी मदद के लिये 3 लाख रुपये की कर्ज गारंटी के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी है।
- गौरतलब है कि कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कई भारतीय कंपनियों को हाल ही में वैक्सीन के उत्पादन में समस्याओं का सामना करना पड़ा था, क्योंकि यूरोप और अमेरिका ने इसके कच्चे माल के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया था।

5. प्रयुक्त खाद्य तेल आधारित बायोडीजल

चर्चा का कारण

- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडियन ऑयल के टिकरीकलां टर्मिलन, दिल्ली से आईओआई योजना के तहत प्रयुक्त खाद्य तेल (Used Cooking Oil-UCO) आधारित बायोडीजल मिश्रित डीजल की पहली आपूर्ति को हरी झंडी दिखाई।

पृष्ठभूमि

- यूसीओ (Used Cooking Oil-UCO) को बायोडीजल में परिवर्तित करने और उद्यमिता के अवसरों को विकसित करने को लेकर एक इकोसिस्टम बनाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 10 अगस्त, 2019 को विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर "प्रयुक्त खाद्य तेल से उत्पादित बायोडीजल" की खरीद के लिए अपनी दिलचस्पी व्यक्त की थी।

प्रमुख बिन्दु

- इंडियन ऑयल के टिकरीकलां टर्मिनल से यूको आधारित बायोडीजल की पहली आपूर्ति से भारत के जैव ईंधन के क्षेत्र विकास को गति मिलेगी और इसका पर्यावरण पर सकारात्मक असर पड़ेगा।
- यह पहल स्वदेशी बायोडीजल आपूर्ति को बढ़ाने, आयात निर्भरता कम करने और ग्रामीण रोजगार को पैदा करके राष्ट्र को पर्याप्त आर्थिक लाभ प्रदान करेगी।
- इस पहल के तहत, तेल कंपनियां पांच साल के लिए समय-समय पर मूल्य की गारंटी देते हैं और संभावित उद्यमियों को दस साल के लिए ऑफ-टेक गारंटी देती हैं। अब तक, इंडियन ऑयल ने 22.95 करोड़ लीटर की कुल क्षमता वाले बायोडीजल प्लांट्स के लिए 23 एलओआई जारी किए है।
- इस पहल के तहत, इंडियन ऑयल को दिल्ली स्थित अपने टर्मिनल में 31 मार्च, 2021 तक 51 किलोलीटर युको-बायोडीजल मिला है। इंडियन ऑयल ने उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में आठ बायोडीजल प्लांट्स का निर्माण शुरू किया है।

प्रयुक्त खाद्य तेल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक

- बार-बार एक ही तेल का रसोई में इस्तेमाल सेहत के लिए हानिकारक होता है। इससे हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरासिस, लीवर से जुड़ी बीमारियां और अल्जाइमर इत्यादि की शिकायत होती है।

बायोडीजल

- बायोडीजल एक वैकल्पिक ईंधन है, जो पारंपरिक या 'जीवाश्म' डीजल की तरह है। यह वनस्पति तेलों, पशु वसा, चरबी और अपशिष्ट खाद्य तेल से उत्पादित किया जाता है।
- बायोडीजल का एक विशिष्ट लाभ इसकी कार्बन तटस्थता है। उदाहरण के लिए तिलहन कार्बनडायऑक्साइड की उतनी ही मात्रा को अवशोषित करता है, जितना ईंधन का दहन होने पर निकलता है। इसके अलावा बायोडीजल तेजी से जैवनिम्निकरण होने वाला और पूरी तरह गैर-जहरीला है।
- बायोडीजल इको फ्रेंडली है और इसे भविष्य का इंधन माना जा रहा है। इसकी सहायता से डीजल वाहनों को चलाने के लिए उनमे किसी प्रकार का तकनीकी परिवर्तन भी नही करना पड़ता है। साथ ही यह सबसे आसान इंधनों में से एक है और सबसे अच्छी बात यह है कि यह खेती में काम आने वाले उपकरणों को चलाने के लिये सबसे उपयुक्त है।

6. पार्कर सोलर प्रोब

चर्चा का कारण

- हाल ही में नासा (NASA) के पार्कर सोलर प्रोब ने शुक्र ग्रह के निकट से गुजरने के दौरान एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल का पता लगाया है। पार्कर सोलर प्रोब ने जिस आवाज को रिकॉर्ड किया है, वह ग्रह शुक्र के ऊपरी वातावरण से आ रही थी।

प्रमुख बिन्दु

- नासा ने पार्कर सोलर प्रोब को सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2018 में लॉन्च किया था। सूर्य की परिक्रमा करते हुए जब यह प्रोब शुक्र के ऊपर से गुजरा तो उसने इस आवाज को सुना। यह लगभग 30 वर्षों में शुक्र ग्रह के वातावरण का पहला प्रत्यक्ष प्रमाण था।
- नए अध्ययन में पाया गया कि शुक्र का ऊपरी वायुमंडल एक सौर चक्र पर बदलाव से गुजरता है। शुक्र को सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है क्योंकि सूरज से अधिक नजदीक होने के कारण बुध का वायुमंडल नष्ट हो चुका है, जिस कारण वह उष्मा को अवशोषित नहीं कर पाता है।
- सूर्य की सतह पर, गैसें लगातार चलती हैं और चुंबकीय क्षेत्र खिंच सकते हैं, मुड़ या उलझ सकते हैं जो सूर्य की सतह पर गति उत्पन्न करते हैं जिसे सौर गतिविधि के रूप में जाना जाता है। यह सौर चक्र के चरणों के साथ भिन्न होता है और औसतन 11 वर्षों तक रहता है. इसलिए हम कह सकते हैं कि सूर्य का नया सौर चक्र हर 11 साल में शुरू होता है।
- गौरतलब है कि नासा (NASA) के पार्कर सोलर प्रोब (Parker Solar Probe) ने इस आवाज को 11 जुलाई, 2020 को रिकॉर्ड किया था। उस समय पार्कर प्रोब और शुक्र के बीच की दूरी लगभग 833 किलोमीटर थी।

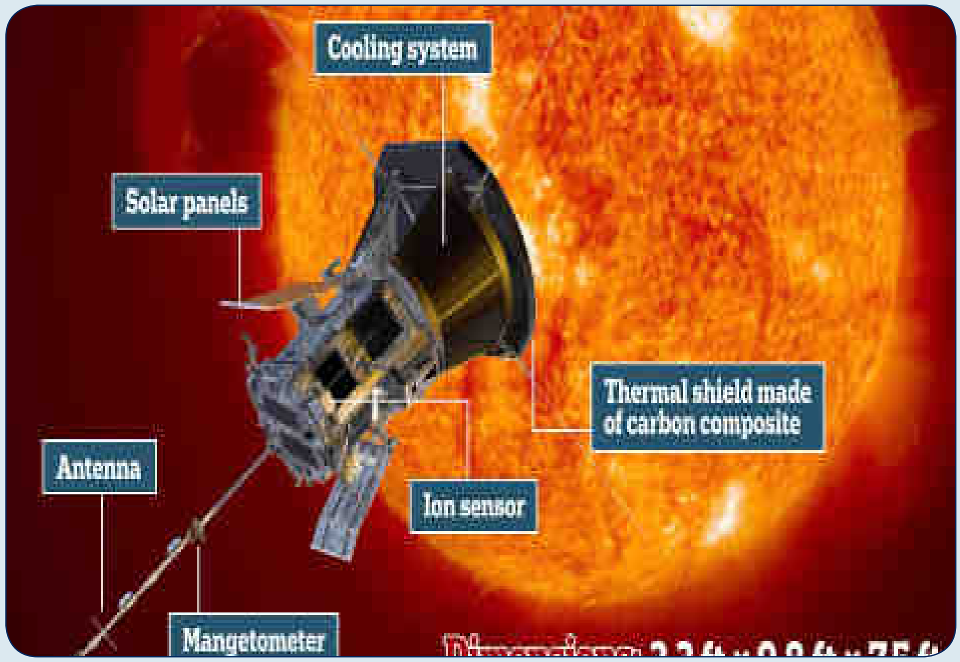

पार्कर सोलर प्रोब (Parker Solar Probe)

- सूर्य के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी जुटाने हेतु कई देशों की स्पेस एजेंसियों ने सोलर मिशन भेजे हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वर्ष 2018 में पार्कर सोलर प्रोब को सूर्य की कक्षा में भेजा था।
- पार्कर सोलर प्रोब का मकसद सूर्य के बाहरी कोरोना का अध्ययन करना है। गौरतलब है कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अपने सोलर मिशन 'आदित्य एल1 मिशन' को वर्ष 2022 में भेजेगी।

शुक्र ग्रह

- शुक्र ग्रह (Venus Planet), सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। यह बुद्ध के बाद सूर्य से दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है। शुक्र ग्रह (Venus Planet) को पृथ्वी की जुड़वाँ बहन (Sister Planet) कहा जाता है क्योंकि इसका द्रव्यमान व आकार लगभग पृथ्वी के आकार के बराबर है।
- इस ग्रह को भोर का तारा (Morning Star) व सांझ का तारा (Evening Star) के नामों से भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह (Venus Planet) पृथ्वी का सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यह ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है।

नासा (National Aeronautics and Space Administration)

- नासा (National Aeronautics and Space Administration) एक सरकारी अमेरिकी अंतरिक्ष संस्थान है।
- इसका गठन 1 अक्टूबर 1958 को किया गया था। नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन, डीसी में है। नासा का गठन द नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एयरोनॉटिक्स के स्थान पर किया गया था।

❖❖❖

सप्ताह के चर्चित व्यक्ति

न्यायाधीश पी.सी. पंत

सुशील चंद्रा

वनीता गुप्ता

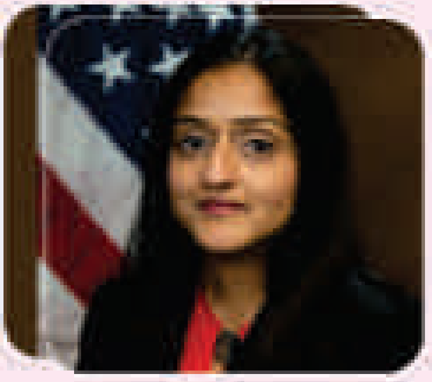

मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना

टी. रबी शंकर

प्रफुल्ल चन्द्र पंत

- हाल ही में प्रफुल्ल चन्द्र पंत को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले, उन्हें 20 सितंबर 2013 को शिलॉन्ग में नवस्थापित मेघालय उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और 12 अगस्त 2014 तक पद पर रहे। 13 अगस्त 2014 से 29 अगस्त 2017 तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एचएल दत्तू (Justice H.L. Dattu) के 2 दिसंबर, 2020 को उनके कार्यकाल पूरा होने के बाद से अध्यक्ष (NHRC) का पद खाली था।

नियुक्ति के बारे में

- NHRC अध्यक्ष को भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए।
- द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स (अमेंडमेंट) एक्ट (TOHRA) की धारा 2 धारा 3 और धारा NHRC में नियुक्ति के लिए नियम निर्धारित करती है। NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत की राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसमें एक समिति शामिल होती है:
- प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता (निचला सदन), राज्यसभा में विपक्ष का नेता (उच्च सदन), लोकसभा अध्यक्ष (निचला सदन), राज्य सभा (उच्च सदन) के उपाध्यक्ष।

नेशनल ह्यूमन राइट्स कमशीन (NHRRC)

- यह एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर, 1993 को हुई थी।

- इसकी स्थापना प्रोटेक्शन ऑफ ह्यून राइट्स एक्ट (PHRA), 1993 के तहत प्रोटेक्शन ऑफ ह्यमन राइट्स (अमेंडमेंट) एक्ट, 2006 के तहत की गई थी।
- NHRC की स्थापना पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप की गई थी।

सुशील चंद्रा

- हाल ही में सुशील चंद्रा ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है। सुशील चंद्रा को 2014 में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था इससे पहले सुनील अरोड़ा देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे थे। सुशील चंद्रा का कार्यकाल अगले साल मई तक जारी रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त के अतिरिक्त दो चुनाव आयुक्त होते हैं।

सुशील चंद्रा के बारे में

- सुशील चंद्रा 1980 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी हैं। वे महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और दिल्ली में कई उच्च पदों पर रह चुके हैं। उन्होंने आईआरएस अधिकारी के तौर पर महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में अपनी सेवाएं दी है।

निर्वाचन आयोग

- निर्वाचन आयोग को चुनाव आयोग भी कहा जाता है। यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। यह भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के

चुनाव का संचालन करता है। 25 जनवरी, 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना संविधान के अनुसार की गई थी। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग से सम्बंधित उपबंध दिए गए हैं।

वनिता गुप्ता

- हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने 21 अप्रैल, 2021 को वनिता गुप्ता द्वारा अमेरिका के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के तौर पर काम करने की पुष्टि की। वे इस भूमिका में सेवा करने वाली पहली भारतीय-अमेरिकी होंगी।

वनिता गुप्ता के बारे में

- वनिता गुप्ता सिविल राईट्स वकील और अमेरिकी सिविल लिबर्टी यूनियन की सर्वोच्च वकील हैं। वह इस पद पर नियुक पाने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला हैं। वनिता गुप्ता का जन्म फिलाडेल्फिया में हुआ था। वह

एक भारतीय-अमेरिकी है। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने वनिता को अमेरिकी न्याय विभाग के नागरिक अधिकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है।

- वनिता गुप्ता ने अपने पूरे करियर के दौरान बड़ी संख्या में लिबरल कार्यकर्ताओं और प्रगतिशील कानून प्रवर्तन अधिकारियों का समर्थन हासिल किया है। 07 जनवरी, 2021 को राष्ट्रपति जो बिडेन ने गुप्ता को एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के तौर पर सेवा देने के लिए नामित किया था।
- गुप्ता ने येल विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ से वर्ष, 2001 में ज्यूरिस डॉक्टर की उपाधि हासिल की थी।

न्यायाधीश एन. वी. रमन्ना

- जस्टिस एन.वी. रमन्ना (Justice NV Ramana) ने 24 अप्रैल 2021 को भारत के 48 वें नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है।
- इससे पहले प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे ने सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश रमना के नाम की सिफारिश की थी। मानदंडों के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति होने के एक महीने पहले अगले सीजेआई का नाम केंद्र सरकार को देना होता है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस रमना का 26 अगस्त 2022 तक कार्यकाल है।

जस्टिस एनवी रमना के बारे में

- जस्टिस एनवी रमना का जन्म 27 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के पोन्नावरम गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस और बैचलर ऑफ लॉ की पढ़ाई की है।
- वे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, सेंट्रल और आंध्र प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। उन्होंने सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, लेबर, सर्विस और इलेक्शन से जुड़े मामले में प्रैक्टिस की है।
- वे कई सारे सरकारी संगठनों में पैनल काउंसलर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। वे आंध्र प्रदेश में एडिशनल एडवोटकेट जनरल भी रह चुके हैं।
- जस्टिस रमना सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच में शामिल थे, जिसने जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट के निलंबन पर तत्काल समीक्षा करने का फैसला सुनाया था। जस्टिस रमना नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एक्जीक्यूटिव चेयरमैन भी हैं।

- वे पहली बार 10 फरवरी 1983 को वकील बने थे। रमना को 27 जून 2000 को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के स्थायी जज के रूप में नियुक्त किया गया था।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ

- संविधान के अनुच्छेद 129 और 142 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय को भारत में किसी भी कानून की अवमानना के लिए किसी को भी दंडित करने की शक्ति दी गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ क्षेत्राधिकार के तीन रूपों से संबंधित हैं। वे मूल क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और सलाहकार क्षेत्राधिकार हैं।

टी. रवि शंकर

- हाल ही में टी रविशंकर को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। वे केंद्रीय बैंक की अनुषंगी कंपनी इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज के चेयरमैन थे।
- उनका कार्यकाल तीन साल का होगा। रवि शंकर इससे पहले आरबीआई के कार्यकारी निदेशक थे। तीन अन्य डिप्टी गवर्नर माइकल डी पात्रा, मुकेश कुमार जैन और राजेश्वर राव है।

टी रवि शंकर के बारे में

- रवि शंकर सितंबर 1990 में आरबीआई में अनुसंधान अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए थे। उन्होंने बीएचयू से विज्ञान एवं सांख्यिकी में स्नात्कोत्तर स्तर की पढ़ाई की।
- वे इंस्टिट्यूट आफ इकोनामिक ग्रोथ से विकास योजना का डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी किए हुए हैं। वे पिछले साल इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज के चेयरमैन बनाए गए थे।
- इससे पहले वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक के साथ भी भारत सरकार की ओर से काम कर चुके हैं।
- उन्होंने नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) से अर्थशास्त्र में एमफिल किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)

- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। शुरू

में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था लेकिन 1937 में स्थायी रूप से इसे मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया था। केंद्रीय कार्यालय वह स्थान है, जहां गवर्नर बैठता है तथा जहां नीतियां तैयार की जाती हैं। 1949 मे राष्ट्रीयकरण के बाद से रिजर्व बैंक पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है।

सप्ताह के चर्चित स्थान

उत्तरी सिक्किम

रुशिकुल्या नदी

प्लेन ऑफ जार्स

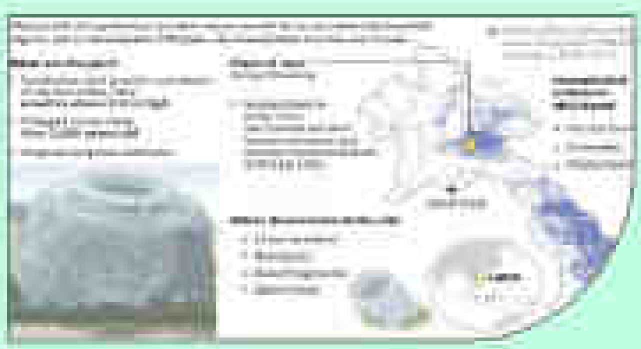

मेघालय में सॉरोपोड्स की खोज

वोरुख

उत्तरी सिक्किम

- भारतीय सेना ने 16,000 फीट की ऊँचाई पर उत्तरी सिक्किम में 56 KVA (किलो वोल्ट एम्पियर) के पहले ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट किया गया है। यह परियोजना, जो वैनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करती है, आईआईटी मुंबई के सहयोग से पूरी हुई है।

भारत में अक्षय ऊर्जा लक्ष्य

- भारत ने 2022 तक 175 GW अक्षय ऊर्जा - 100 GW सोलर, 60 GW विंड, 10 GW बायो-एनर्जी, 5 GW स्मॉल हाइड्रो का लक्ष्य रखा है।
- वर्तमान में, RE अक्षय ऊर्जा क्षमता के 93 GW भारत में स्थापित किए गए हैं।

वैनेडियम (Vanadium)

- जनवरी 2021 में, वनैडियम अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया था। यह भारत में वनैडियम की पहली खोज थी।
- भारत विश्व में वैश्विक वेनेडियम उत्पादन का 4% उपभोग करता है।
- यह 60 विभिन्न खनिजों और अयस्कों में पाया जाता है जिसमें कारनोटाइट, वनाडेट, रोसकोलाइट, पेट्रोनाइट शामिल हैं।
- वैनेडियम का उपयोग स्टील मिश्र धातु, अंतरिक्ष वाहन, परमाणु रिएक्टर आदि बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग गर्डर्स, पिस्टन रॉड बनाने में भी किया जाता है।वैनेडियम रेडॉक्स बैटरी का उपयोग सुपरकंडक्टिंग

मैग्नेट में किया जाता है। उनका उपयोग ऊर्जा के विश्वसनीय अक्षय स्रोतों को बनाने के लिए भी किया जाता है।
- वनैडियम का रंग सिल्वर है। यह एक संक्रमण कालीन धातु है, जो गर्मी और बिजली का अच्छा संवाहक है।

रुशिकुल्या नदी

- ओडिशा में स्थित रुशिकुल्या नदी का मुहाना गहिरमाथा के बाद भारत में ओलिव रिडले कछुओं का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। इस साल, रशिकुल्या नदी के मुहाने के पास लाखों ओलिव रिडले समुद्री कछुए संभवत: घोसलें नहीं बना पाएंगे, क्योंकि घोंसला बनाने की प्रक्रिया का समय समाप्त होने वाला है। मार्च 2020 में, एक ही स्थान पर 3 लाख से अधिक कछुओं ने घोंसला बनाया था।

ओलिव रिडले

- ओलिव रिडले समुद्री कछुओं (Lepidochely Olivacea) को प्रशांत ओलिव रिडले समुद्री कछुओं के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया के सबसे छोटे समुद्री कछुए हैं।
- यह मुख्य रूप से प्रशांत, हिन्द और अटलांटिक महासागरों के गर्म जल में पाए जाने वाले समुद्री कछुओं की एक मध्यम आकार की प्रजाति है। ये माँसाहारी होते हैं।
- पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने वाले विश्व का सबसे पुराने और सबसे बड़े संगठन आईयूसीएन रेड लिट में इसे अतिसंवेदनशील प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है।
- ओलिव रिडले कछुए हजारों किलोमीटर की यात्रा कर ओडिशा के गंजम तट पर अंडे देने आते हैं और फिर इन अंडों से निकले बच्चे समुद्री मार्ग से वापस हजारों किलोमीटर दूर अपने निवास-स्थान पर चले जाते हैं।
- उल्लेखनीय है कि लगभग 30 साल बाद यही कछुए जब प्रजनन के योग्य होते हैं तो ठीक

उसी जगह पर अंडे देने आते हैं, जहाँ उनका जन्म हुआ था।
- दरअसल अपनी यात्रा के दौरान भारत में गोवा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश के समुद्री तटों से गुजरते हैं लेकिन प्रजनन करते और घर बनाने के लिये ओडिशा के समुद्री तटों की रेत को ही चुनते हैं।

'प्लेन ऑफ जार्स'

- प्लेन ऑफ जार्स (Plain of Jars) उत्तरी लाओस में स्थित एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है। इसमें घाटियों और जियांगखोआंग पठार (Xiangkhoang Plateau) की तलहटी के आसपास बिखरे हजारों पत्थर के जार हैं। हाल ही में हुए एक शोध के अनुसार, प्लेन

ऑफ जार (Plain of Jars) को संभवतः एक दफन स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। शोध के अनुसार यह जार 3,000 साल से अधिक पुराने हो सकते हैं।

लाओस के बारे में

- लाओस दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। इसकी सीमाएं उत्तर पश्चिम में म्यान्मार और चीन से, पूर्व में कंबोडिया, दक्षिण में वियतनाम और पश्चिम में थाईलैंड से मिलती हैं। इसे हजार हाथियो की भूमि भी कहा जाता है। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र स्थल-रुद्ध देश है।

मेघालय में सॉरोपोड्स की खोज

- हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (Geological Survey of India) के शोध कर्ताओं ने सॉरोपोड डायनासोर (Sauropod dinosaurs) के जीवाश्म हड्डी के टुकड़ों की खोज की है। वे 100 मिलियन वर्ष के पुराने हैं। इन डायनासोर की हड्डियाँ मेघालय जिले के पश्चिम खासी पहाड़ियों (West Khasi Hills) में पाई गई थीं। यह इस क्षेत्र में सॉरोपोड की खोज की पहली घटना है।

सॉरोपोड्स (Sauropods)

- सॉरोपोड्स की गर्दन लंबी, छोटे सिर, लंबी पूंछ और स्तंभ की तरह 4 पैर होते थे।
- मेघालय ऐसा 5वां राज्य बन गया है जहाँ सॉरोपोड्स के साक्ष्य मिले हैं, इससे पहले गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में इस तरह के साक्ष्य मिले हैं।
- उल्लेखनीय है कि पहली डायनासोर की हड्डी की खोज जबलपुर छावनी के बड़ा सिमला हिल (Bara Simla Hill) में की गई थी।

भारत में डायनासोर

- भारत में डायनासोर्स ट्राइसिक काल के अंत से लेकर क्रेटेशियस काल तक मौजूद थे।

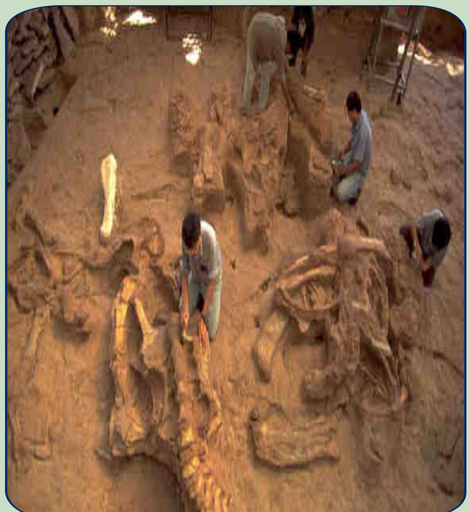

- राजासौरस डायनासोर (Rajasaurus dinosaur) भारत में उत्पन्न हुआ था।
- भारत में पाए जाने वाले सभी डायनासोरों में से, बारापासॉरस (Barapasaurus) भारत में सबसे बड़ा था। यह चार मीटर ऊँचा और 24 मीटर लंबा था। सबसे खतरनाक टायरानोसॉरस रेक्स (Tyrannosaurus rex) था।

पृथ्वी पर डायनासोर की विलुप्ति के कारण

- वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी पर से डायनासोर की विलुप्ति का मुख्य कारण उल्कापिण्ड का गिरना था, जिसने पृथ्वी की जलवायु परिस्थितियों को बदल दिया। इन जलवायु परिस्थितियों में डायनासोर जीवित नहीं रह सकते थे। इसके अलावा उल्कापिंड के प्रभाव के कारण बनाई गई खाद्य श्रृंखला के असंतुलन से डायनासोर भुखमरी के कारण भी मारे गये। उल्कापिंड के प्रभाव से कई जानवर मारे गए और अधिकांश जंगल जल गए।

वोरुख

- हाल ही मे ताजिकिस्तान के सुग्ग प्रांत और किर्गिस्तान के दक्षिणी बटकेन प्रांत के बीच 'वोरूख' नामक सीमाई क्षेत्र पर विवाद उत्पन्न हो गया था। इस विवाद का प्रमुख कारण यह है कि दोनों देश इस्फारा नदी पर स्थित एक जलाशय और पम्पिंग स्टेशन पर अपना दावा करते हैं।
- उत्तरी ताजिकिस्तान में एक 'वोरूख' एक प्रशासकीय क्षेत्र है। प्रशासकीय क्षेत्र को तजाकिस्तान के स्थानीय भाषा में 'जमोट' भी कहते हैं। यह किर्गिस्तान से घिरा हुआ क्षेत्र है।

- मध्य एशियाई देश ताजिकिस्तान में 'जमोट' कम्यून या नगरपालिकाओं की भांति तृतीय स्तर की प्रशासनिक इकाई होते है।

❖❖❖

सप्ताह के प्रमुख राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय दिवस

विश्व अस्थमा दिवस

अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस : 1 मई

विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस : 3 मई

विश्व रेडक्रॉस दिवस: 8 मई

विश्व अस्थमा दिवस

- विश्व अस्थमा दिवस हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में अस्थमा की बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। हर साल विश्व अस्थमा दिवस का आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा (Global Initiative for Asthma) द्वारा किया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम 'अनकवरिंग अस्थमा मिसकन्सेप्सन' (Uncovering Asthama Misconceptions) है।

आवश्यकता

- WHO के अनुसार, पूरी दुनिया में लगभग 235 मिलियन लोग अस्थमा से पीड़ित हैं। यह गैर-संचारी रोगों में से एक है। बच्चों में अस्थमा सबसे आम बीमारी है।

अस्थमा के लिए वैश्विक पहल

- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विभिन्न स्वास्थ्य संस्थान के सहयोग से 1993 में अस्थमा के लिए वैश्विक पहल शुरू की थी। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को चिकित्सा दिशानिर्देश प्रदान करती है।

भारत में अस्थमा

- भारत में लगभग 6% बच्चे और 2% वयस्क अस्थमा के कारण प्रभावित हैं। भारत में अस्थमा का इलाज किया जाता है और निदान किया जाता है।

इतिहास

- पहला विश्व अस्थमा दिवस 1998 में 35 से अधिक देशों में मनाया गया था। पहला विश्व अस्थमा दिवस स्पेन में विश्व अस्थमा बैठक के संयोजन में मनाया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस : 1 मई

- मजदूर हमारे समाज का वह हिस्सा है जिस पर समस्त आर्थिक उन्नति टिकी हुई है। वर्तमान समय के मशीनी युग में भी उनकी महत्ता कम नहीं हुई है। उदाहरण के लिए, उद्योग, व्यापार, कृषि, भवन निर्माण, पुल एवं सड़कों का निर्माण आदि समस्त क्रियाकलापों में मजदूरों के श्रम का योगदान महत्त्वपूर्ण होता है।
- दुनिया में सबसे पहले 1 मई 1886 को अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत हुई थी। अमेरिका के मजदूरों ने 8 घंटे काम करने के लिए हड़ताल की थी। इसी हड़ताल के दौरान शिकागो के "हेय मार्किट" में बम धमाका हुआ था। जिसके कारण पुलिस ने मजदूरों पर गोली चला दी और कुछ मजदूर मरे गए स उस समय अमेरिका पर इन घटनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन बाद में 8 घंटे काम करने के समय को निश्चित कर दिया गया। भारत में सबसे पहले 1923 में श्रमिकों द्वारा मनाया गया था। किसान मजदूर पार्टी के नेता कामरेड "सिंगरावेलू चेट्यार" ने इसकी शुरूआत की थी उल्लेखनीय है कि मद्रास हाईकोर्ट सामने इस दिन को पूरे भारत में "मजदूर दिवस" के रूप में मनाने का संकल्प लिया और छुट्टी का ऐलान किया था।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस : 3 मई

- विश्व स्तर पर 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आयोजित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को वर्ष 1993 में अन्तराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना प्रस्तावित किया था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस Windhoek Declaration की वर्षगांठ पर हर साल 3 मई को मनाया जाता है। यह दिवस प्रेस की आजादी के मौलिक सिद्धांतों को उजागर करने तथा पत्रकारों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हर साल मनाया जाता है।

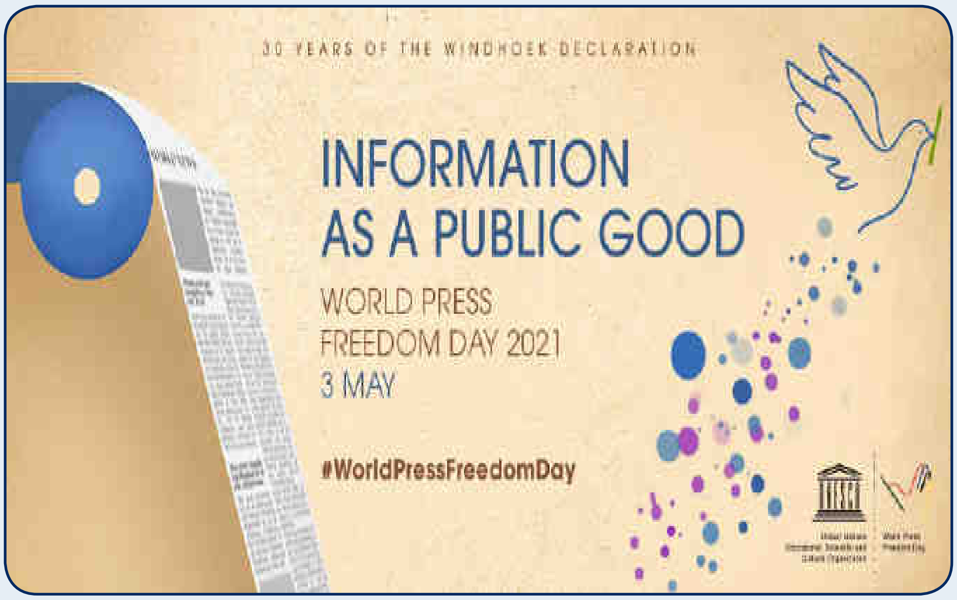

भारत में प्रेस की स्थिति

- भारत जैसे विकासशील देशों में मीडिया पर जातिवाद और सम्प्रदायवाद जैसे संकुचित विचारों के खिलाफ संघर्ष करने और गरीबी तथा अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई में लोगों की सहायता करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लोगों का एक बहुत बड़ा वर्ग पिछड़ा और अनभिज्ञ है, इसलिये यह और भी जरूरी है कि आधुनिक विचार उन तक पहुंचाए जाएं और उनका पिछड़ापन दूर किया जाए, ताकि वे सजग भारत का हिस्सा बन सकें।
- गौरतलब है कि 20 अप्रैल, 2021 को जारी नवीनतम विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक (World Press Freedom Index) 2021 में 180 देशों में से भारत 142वें स्थान पर है जबकि नॉर्वे का शीर्ष स्थान है।

विश्व रेडक्रॉस दिवस: 8 मई

- इंटरनैशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस (आईसीआरसी) की स्थापना 1863 में हुई थी। यह संगठन सशस्त्र हिंसा और युद्ध में पीड़ित लोगों एवं युद्धबंदियों के लिए काम करती है। यह उन कानूनों को प्रोत्साहित करती है जिससे युद्ध पीड़ितों की सुरक्षा होती है।

वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के बारे में

- नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता हेनरी डुनैंट का जन्म 8 मई, 1828 को हुआ था । हेनरी डुनैंट ने साल 1863 में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में रेड क्रॉस कमेटी इंटरनेशनल की स्थापना की।
- वर्ष 1934 में, 15 वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में रेड क्रॉस डे के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया गया था। उसी सम्मेलन में प्रतिवर्ष 8 मई, 1948 को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाए जाने की मंजूरी दी गई थी। विश्व रेड क्रॉस दिवस को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस के रूप में भी जाना जाता है।

❖❖❖

सप्ताह के प्रमुख तथ्य

01

03

05

01 “MACS 1407” क्या है, जो हाल ही में खबरों में था?

सोयाबीन की किस्म

02 किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है?

तमिलनाडु

03 ज्वालामुखी ‘माउण्ट सिनाबंग’ किस देश में स्थित है?

इण्डोनेशिया

04 हाल ही में खबरों में रहा चीन के पहले मार्स रोवर का नाम क्या है?

झुरोंग

05 ‘पुतोल नाच’, जो हाल ही में खबरों था, किस राज्य की पारंपरिक कठपुतली कला (string puppetry art) है?

असम

06 कौन-से फिल्म को ऑस्कर अवॉर्ड्स (2021) मिला है?

‘नोमैडलैंड’ (Nomadland)

07 भारत में किस महिला मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक है?

ममता बनर्जी

स्वयं को जाँचें
(वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

1. "माउंटेन्स टू मैंग्रोव्स - अ जर्नी ऑफ 1000 किलोमीटर"

प्र. हाल ही में चर्चित "माउंटेन्स टू मैंग्रोव्स - अ जर्नी ऑफ 1000 किलोमीटर" के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने 'देखो अपना देश' (Dekho Apna Desh) की वेबीनार श्रृंखला (Webinar series) के अंतर्गत "माउंटेन्स टू मैंग्रोव्स - अ जर्नी ऑफ 1000 किलोमीटर" (Mountains to Mangroves - A Journey of 1000 Kilometers) नामक वेबीनार आयोजित किया है।
2. इस वेबीनार में पर्वतों से मैंग्रोव तक 1000 किलोमीटर की यात्रा दो सबसे सुरम्य राज्यों- गुजरात और केरल पर केंद्रित थी।
3. यह यात्रा हिमालय पर्वतश्रेणी के सिक्किम से शुरू होकर पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग होते हुए दक्षिण में तटीय क्षेत्र में स्थित गंगा के मैदानों से विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन में पूरी हुई।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2 और 3
(C) 1, 2 और 3
(D) केवल 2

Ans: (A)

व्याख्या: हाल ही में भारत सरकार ने "माउंटेन्स टू मैंग्रोव्स- अ जर्नी ऑफ 1000 किलोमीटर" (Mountains to Mangroves - A Journey of 1000 Kilometers) नामक वेबीनार आयोजित किया है। इस वेबीनार में पर्वतों से मैंग्रोव तक 1000 किलोमीटर की यात्रा दो सबसे सुरम्य राज्यों- पश्चिम बंगाल और सिक्किम पर केंद्रित थी न कि गुजरात और केरल अतः कथन-2 गलत है। इस संदर्भ में शेष दोनों कथन सही हैं। इस प्रकार **उत्तर (A)** होगा।

2. जलवायु परिवर्तन के चलते पृथ्वी की धुरी में आ रहा बदलाव

प्र. पृथ्वी की धुरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. पृथ्वी जिस धुरी अथवा अक्ष पर घूमती है, वह काल्पनिक रेखा है, जो पृथ्वी के केंद्र से होकर उसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती है।
2. पृथ्वी का यह अक्ष अपने कक्ष के तल के साथ 66 डिग्री अंश का कोण बनाता है।
3. पृथ्वी का यह अक्ष सदैव बदलता रहता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं ?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 1 और 3
(C) उपर्युक्त में से कोई नहीं
(D) उपर्युक्त सभी

Ans: (A)

व्याख्या: अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन (AGU) के 'जर्नल जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में छपे नए शोध के अनुसार 1990 के दशक के बाद से जलवायु परिवर्तन और तापमान में हो रही वृद्धि के चलते दुनिया भर में ग्लेशियर बड़ी तेजी से पिघल रहे हैं जिसका असर पृथ्वी की धुरी पर पड़ रहा है और उसके झुकाव में वृद्धि हो रही है। उल्लेखनीय है कि पृथ्वी का यह अक्ष सदैव एक ओर ही झुका रहता है। न कि सदैव बदलता रहता है। इस प्रकार कथन 3 गलत है, पृथ्वी की धुरी के संदर्भ में शेष दोनों कथन सही हैं। अतः **उत्तर (A)** है।

3. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021

प्र. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. गृह मंत्रालय के अनुसार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 में संशोधन से दिल्ली में निर्वाचित सरकार के संवैधानिक व विधिक दायित्वों में किसी तरह का बदलाव नहीं आया है।
2. यह संशोधन अधिनियम दिल्ली की निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल (एलजी) के उत्तरदायित्वों को परिभाषित करेगा और विधायिका व कार्यपालिका के बीच "एक सौहार्दपूर्ण संबंध बनाएगा"।
3. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 को लोकसभा द्वारा 22 मार्च, 2021 और राज्य सभा द्वारा 24 मार्च, 2021 को पारित किए जाने के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा 28 मार्च, 2021 को अनुमोदित किया गया था।
4. इस संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 21, 24, 33 और 44 में संशोधन किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही हैं/है?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 3 और 4
(C) 1, 2 और 3
(D) उपर्युक्त सभी

Ans: (D)

व्याख्याः हाल ही में गृह मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 [Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Act, 2021] के तहत स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी क्षेत्रों में दिल्ली की चुनी हुई सरकार के संवैधानिक और कानूनी जिम्मेदारियों में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ है। इस संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। अतः **उत्तर (D)** होगा।

4. भारत- यूनाइटेड किंगडम वर्चुअल शिखर सम्मेलन

प्र. भारत- यूनाइटेड किंगडम वर्चुअल शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?

(A) भारत के प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बीच हाल ही में एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसे भारत- यूनाइटेड किंगडम वर्चुअल शिखर सम्मेलन (India-United Kingdom Virtual Summit) नाम दिया गया है।

(B) भारत-यूनाइटेड किंगडम वर्चुअल शिखर सम्मेलन में एक महत्वाकांक्षी 'रोडमैप 2030' (Roadmap 2030) को अपनाया गया।

(C) यह रोडमैप अगले 25 वर्षों में दोनों देशों के लोगों के बीच पारस्परिक संपर्कों, व्यापार एवं अर्थव्यवस्था, रक्षा व सुरक्षा, जलवायु कार्रवाई और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गहन व मजबूत जुड़ाव का मार्ग प्रशस्त करेगा।

(D) दोनों देशों के राजनेताओं ने कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति के खिलाफ लड़ाई में आपसी सहयोग पर भी चर्चा की।

Ans: (C)

व्याख्याः हाल ही में भारत- यूनाइटेड किंगडम वर्चुअल शिखर सम्मेलन (India-United Kingdom Virtual Summit) का आयोजन हुआ है। यह रोडमैप अगले 10 वर्षों (न कि 25 वर्षों के लिए) में दोनों देशों के लोगों के बीच पारस्परिक संपर्कों, व्यापार एवं अर्थव्यवस्था, रक्षा व सुरक्षा, जलवायु कार्रवाई और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गहन व मजबूत जुड़ाव का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस प्रकार कथन **(c)** गलत है।

5. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में रणनीतिक विनिवेश

प्र. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में रणनीतिक विनिवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs) ने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में रणनीतिक विनिवेश के साथ-साथ प्रबंधन नियंत्रण (management control) के हस्तांतरण को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
2. भारत सरकार और एलआईसी के पास आईडीबीआई बैंक की 94% से भी अधिक इक्विटी (भारत सरकार 45.48%, एलआईसी 49.24%) है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही हैं/है?

(A) केवल 1

(B) केवल 2

(C) 1 और 2 दोनों

(D) न तो 1 न ही 2

Ans: (c)

व्याख्याः हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (IDBI Bank Limited) में रणनीतिक विनिवेश (strategic disinvestment) और प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण (transfer of management control) को मंजूरी दे दी है। इस संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही हैं अतः **उत्तर (C)** होगा।

6. नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम (NGFS)

प्र. नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम (NGFS) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. 'नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम' (Network for Greening Financial System-NGFS) 83 केंद्रीय बैंकों और वित्तीय पर्यवेक्षकों का एक नेटवर्क है।
2. 'नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम' (एनजीएफएस) की स्थापना 2017 में हुई थी।
3. वर्तमान में 'नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम' (एनजीएफएस) के सचिवालय को 'बंक डी फ्रांस' (Banque de France) द्वारा होस्ट किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल 1

(B) केवल 2 और 3

(C) 1 , 2 और 3

(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

व्याख्याः हाल ही में 'नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम' (Network for Greening Financial System-NGFS) में भारत का भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) शामिल हुआ है। 'नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम' के संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। अतः **उत्तर (C)** होगा।

7. वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट - 2021

प्र. वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट - 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. 'वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट-2021' (Global Forest Goals Report-2021) को संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएनओ) द्वारा जारी किया गया है।
2. 'वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट-2021' में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी ने वनों के प्रबंधन में विभिन्न देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा दिया है।
3. वनों पर आश्रित समुदायों ने कोविड-19 महामारी के चलते ना सिर्फ अपने रोजगार को खोया है बल्कि उनकी आय में भी कमी आई है।
4. इस महामारी ने समाज के संवेदनशील वर्गों (यथा-महिलाएँ आदि) के लिए मौसमी रोजगार में भारी कमी की है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 3 और 4
(C) केवल 2 और 4
(D) उपर्युक्त सभी

Ans: (D)

व्याख्या: हाल ही में 'वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट-2021' (Global Forest Goals Report-2021) को जारी किया गया है।'वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट-2021' (Global Forest Goals Report&2021) को संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएनओ) द्वारा जारी किया गया है। दरअसल 'वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट-2021' को संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (Department of Economic and Social Affairs) द्वारा निर्मित किया गया है। इस संदर्भ में सभी कथन सही हैं। अतः **उत्तर (D)** होगा।

8. एशियाई विकास आउटलुक - 2021

प्र. एशियाई विकास आउटलुक - 2021, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. एशियाई विकास बैंक (ADB) ने एशियाई विकास आउटलुक-2021 (Asian Development Outlook-2021) रिपोर्ट में कहा है कि भारत में इस समय कोविड-19 की दूसरी लहर चल रही है; जो भारत के आर्थिक सुधारों को 'जोखिम' में डाल सकती है।
2. इस रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी में 7% वृद्धि दर का ही अनुमान लगाया गया है।
3. वहीं एशियाई विकास आउटलुक-2021 रिपोर्ट में एशिया महाद्वीप के संदर्भ में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में विकासशील एशिया की आर्थिक वृद्धि दर 7.3% के आसपास रहेगी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 3
(D) 1, 2 और 3

Ans: (D)

व्याख्या: हाल ही में एशियाई विकास बैंक (ADB) ने एशियाई विकास आउटलुक-2021 (Asian Development Outlook-2021) रिपोर्ट को जारी किया है। एशियाई विकास आउटलुक-2021 के संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। अतः **उत्तर (D)** होगा।

9. 'प्रतिरक्षण रणनीति- 2030'

प्र. हाल ही में चर्चित 'प्रतिरक्षण रणनीति-2030' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये?

1. प्रतिरक्षण रणनीति- 2030 ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान पर आधारित है।
2. इसका उद्देश्य ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान के उन लक्ष्यों को संबोधित करना है जो 'वैक्सीन दशक' (2011-20) की वैश्विक टीकाकरण रणनीति के हिस्से के रूप में पूरे किये जाने थे।
3. यह सात रणनीतिक प्राथमिकताओं के एक वैचारिक ढांचे पर आधारित है

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) 1, 2 और 3
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

व्याख्या: हाल ही में संयुक्त राष्ट्र और अन्य एजेंसियों द्वारा विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह के दौरान प्रतिरक्षण रणनीति- 2030 (UN's Immunisation Agenda 2030) को लॉन्च किया है। यह संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य सतत् विकास लक्ष्यों (विशेष रूप से सतत् विकास लक्ष्य-3 जिसमे बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण शामिल है) को प्राप्त करने में योगदान देगा। प्रतिरक्षण रणनीति के संदर्भ में सभी कथन सही है। अतः **उत्तर C)** होगा।

10. जी-7 देशों द्वारा चीन के विरुद्ध सामूहिक मोर्चा बनाने का प्रयास

प्र. जी-7 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. जी-7 की पहली बैठक 1975 में हुई थी।
2. जी-7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमरीका शामिल हैं।
3. जी-7 में रूस वर्ष 1976 में शामिल हुआ था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) 1, 2 और 3

(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (A)

व्याख्या: हाल ही में ब्रिटेन की मेजबानी में जी-7 देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा तेजी से मुखर चीन के विरूद्ध एक सामूहिक मोर्चा बनाने की संभावनाओं पर चर्चा की। विदित हो कि जी-7 में वर्ष 1976 में कनाडा शामिल हुआ था न कि रूस। इस प्रकार कथन 3 गलत है। जी-7 के संदर्भ में शेष कथन सही हैं अत: उत्तर (A) होगा।

❖❖❖

स्वयं को जाँचें
(विषयनिष्ठ प्रश्न)

01

03

05

01 वर्तमान समय में विश्व के अनेक देशों द्वारा कोविड-19 के कारण यात्रा पर प्रतिबंध लगाए गये हैं। यह प्रतिबंध भारत को किस हद तक प्रभावित करते हैं? परीक्षण कीजिए-

02 क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि भारत ने कोविड-19 संकट के दौर में भी प्रवासियों की सहायता करने में महत्वपूर्ण ट्रैक रिकार्ड स्थापित किया है?

03 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता प्राप्त करने के लिए भारत अपने संघर्ष में कहाँ तक सफल हुआ है। चर्चा कीजिए।

04 कोविड-19 टीकों के पेटेंट को रद्द किया जाना क्या गलत मिसाल कायम करेगा? समालोचनात्मक परीक्षण करें।

05 हाल के दिनों में भारत-यूनाइटेड किंगडम संबंधों में नई ऊर्जा देखने को मिली है। इस नये संबधों में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को रेखांकित करें।

06 पहाड़ तथा पठार किसी स्थान विशेष की जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। व्याख्या कीजिए।

07 जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक क्षेत्र में कौन-कौन से बदलाव हाल के दिनों में परीलक्षित हुए हैं? इससे वैश्विक मौसम प्रतिरूप (Pattern) पर क्या प्रभाव पड़ेगा। स्पष्ट कीजिए।

08 भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास में 'पाल काल' अति महत्वपूर्ण है। विश्लेषण कीजिए।

09 क्या आप इस बात से सहमत हैं कि लार्ड कर्जन की नीतियों ने राष्ट्रीय आन्दोलन में दूरगामी परिणाम लाये, परीक्षण कीजिए।

10 सामाजिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के क्रम में, विशेषकर जराचिकित्सा तथा मातृ स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सुदृढ़ और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल संबंधी नीतियों की आवश्यकता है। विवेचन कीजिए।

ध्येय IAS
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA–9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

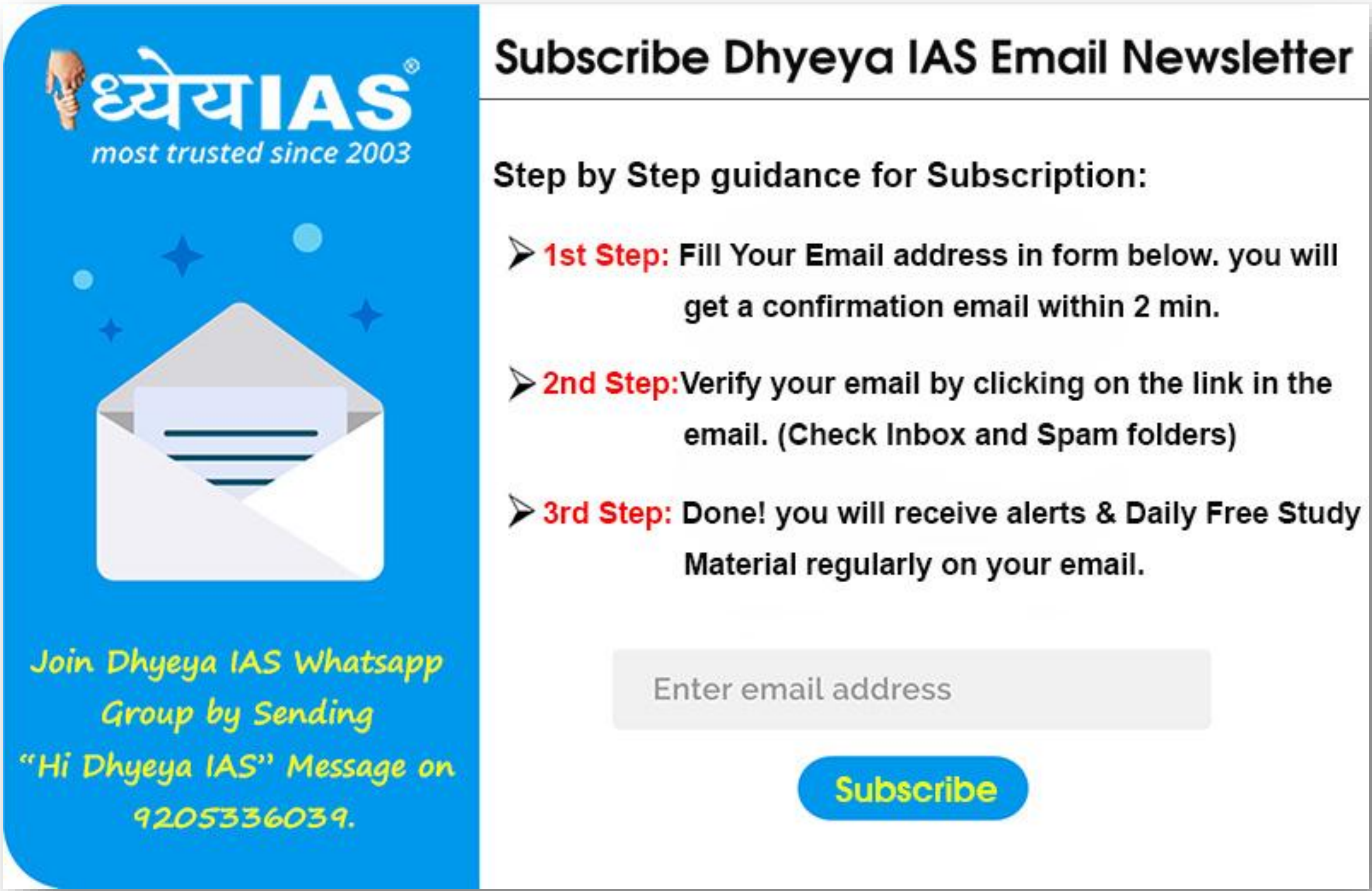

ध्येयIAS
most trusted since 2003
Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ADMISSIONS OPEN

FOR NEW ONLINE BATCH

IAS PRE-CUM-MAINS

PCS

OPTIONAL

HINDI & ENGLISH MEDIUM

Call: 9205962002 9506256789 | Whatsapp: 9205274741 | Visit: dhyeyaias.com